● वर्ष-5
● अंक-265
रायपुर, मंगलवार
23 जून 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> वित्त मंत्री चौधरी ने प्रबुद्धजनों...

राष्ट्रीय कर्तव्य विषय पर सुदर्शन प्रेरणा मंच का व्याख्यान

भ्रष्ट लोगों की समाज में प्रतिष्ठा न हो: मुकुल कानिटकर

रायपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंचम सरसंघचालक स्व. कुप्पाहली सीतारमैया सुदर्शन की जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय व्याख्यान में मुख्य वक्ता मुकुल कानिटकर ने कहा, हिंदू समाज का आधार मैं से हम की ओर जाना है। इस यात्रा में पांच परिवर्तन के उद्देश्य तय किया गया है जिसमें स्वदेशी का चिंतन है, संवाद से कुटुंब परिवार की शक्ति बढ़ाना, सामाजिक समरसता की संकल्पना है, पर्यावरण के प्रति संवेदना और राष्ट्रीय कर्तव्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता शामिल है। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघचालक डॉ टोपलाल वर्मा एवं मुख्यातिथि अनुराग पांडे थे। संचालन साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक

शर्मा ने किया। कार्यक्रम संयोजिका शील शर्मा ने स्वागत भाषण दिया।

मुकुल कानितकर ने राष्ट्रीय कर्तव्य, स्वार्थ ही देशद्रोह विषय पर बोलते हुए कहा, हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है, सभी कोशिकाएं मिलकर प्रत्येक अंग बनते हैं, जो अपना अपना कार्य करते हैं इसलिए जीवन चलता है। इसी प्रकार देश भी सभी व्यक्ति से मिलकर बनता है, मिलकर अपना अपना कार्य करेंगे तो राष्ट्र शक्तिशाली होगा। यही प्रत्येक व्यक्ति का देश के प्रति कर्तव्य है। जैसे एक कोशिका के स्वार्थी हो जाने से शरीर बीमार और कमजोर हो जाएगा इसी प्रकार एक व्यक्तिव स्वार्थी हो जाने से देश कमजोर हो जाता है।

उन्होंने कहा, देश के प्रति कर्तव्य नहीं करने के कारण समाज, व्यवस्था में अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इसे समाज में मान्यता मिल गई है। इस भ्रष्टाचार से मुक्ति का उपाय यही है कि समाज ऐसे लोगों को दंडित करे, बहिष्कार करे। व्यक्ति अपने स्वार्थ में देश का नुकसान करे उसे समाज प्रतिष्ठा न दे।

मुकुल कानिटकर ने कहा, संघ को लेकर विवाद खड़े वे लोग करते हैं जिन्हें संघ की समझ नहीं है। संघ हिंदू समाज को संगठित करने की यात्रा है। संघ की शताब्दी वर्ष कोई उत्सव का अवसर नहीं है बल्कि समाज परिवर्तन के अपने कार्य के सिंहावलोकन करने का अवसर है। राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माणकार ही संघ का लक्ष्य है। संघ की स्थापना भारत के स्वाधीन होने के बाद भारत का स्व तंत्र कैसे विकसित हो, शक्तिशाली कैसे बने इस विचार को लेकर कार्य प्रारंभ करने के लिए किया था। इसके लिए हिंदू समाज को संगठित करना आवश्यक है, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना आवश्यक है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डॉ हेडगेवार ने संघ की स्थापना की। यह भारतीय स्वाधीनता का सशस्त्र आंदोलन, अहिंसा और सत्याग्रह के बाद तीसरा आंदोलन था। कार्यक्रम के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रान्त के संघचालक डॉ टोपलाल वर्मा ने स्व. सुदर्शन जी का स्मरण करते हुए कहा, उनका जीवन और विचार देश को प्रेरणास्पद है। मुख्य अतिथि अनुराग पांडे ने कहा, नागरिक कर्तव्य नहीं होने के कारण जगह जगह गंदगी, यातायात की समस्या, भ्रष्टाचार जैसी अव्यवस्था फैलती है।

भारत अब केवल तेज अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक वैश्विक महाशक्ति

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत का हुंकार भरा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत न केवल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बल्कि वैश्विक मंच पर एक बेहद विश्वसनीय और भरोसेमंद ताकत बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि आज भारत अगले 1,000 वर्षों के भविष्य की पटकथा लिख रहा है और यही नए भारत का दुनिया के लिए सबसे बड़ा भरोसा यानी गारंटी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश की सोच में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव आया है। पहले जहां लोग सोचते थे कि यह काम कभी नहीं हो सकता, वहीं आज हर देशवासी का भरोसा है कि यह काम होकर रहेगा। सोच में आया यह बदलाव ही नए भारत की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

नेशन फर्स्ट हमारा सर्वोच्च मंत्र, जी-7 देशों को भी है भरोसा- पीएम मोदी

हाल ही में संपन्न हुए जी-7 शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं कुछ ही दिन पहले जी-7 समिट से लौटा हूं। दुनिया का हर बड़ा नेता और हर देश आज यह अच्छी तरह समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट राष्ट्र प्रथम ही उसका सर्वोच्च मंत्र और मार्गदर्शक सिद्धांत है।एक मीडिया चैनल के कार्यक्रम में मौजूद जाने-माने उद्यमी और जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब देश के उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ काम करते हैं, तो बड़े संस्थानों का निर्माण होता है और देश समृद्ध बनता है। उन्होंने फ्रांस के विवाटेक का अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि वहां जोहो के स्टॉल पर यूरोपीय युवाओं की भारी भीड़ देखकर उन्हें बेहद गर्व की अनुभूति हुई थी।

रायपुर। किसानों की समृद्धि, गांवों का विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी संकल्प के साथ राज्य सरकार पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए प्रदेश में विकास और सुशासन के नए अध्याय लिख रही है। मुख्यमंत्री ने आज राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन एवं लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे।

भारत ने रूस से भरा तेल का भंडार

नई दिल्ली। ईरान और अमेरिका के बीच एमओयू साइन होने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य होने तक भारत ने जून में रूस और संयुक्त अरब अमीरात से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है. भारतीय रिफाइनरियों ने खाड़ी क्षेत्र से आपूर्ति पूरी तरह बहाल होने से पहले अपना ऑयल स्टोरेज सुरक्षित करने की रणनीति अपनाई. मैरीटाइम और कमोडिटी इंटेलिजेंस फर्म क्लेपेर के आंकड़ों के मुताबिक, जून में 19 तारीख तक भारत ने रूस से औसतन 26.6 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया, जबकि मई में यह 19.1 लाख बैरल प्रतिदिन था. इसके साथ ही रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है. संयुक्त अरब अमीरात से आयात जून में 6.36 लाख बैरल प्रतिदिन रहा, जो मई के रिकॉर्ड 6.44 लाख बैरल प्रतिदिन से थोड़ा कम है।

पंजाब का युवा करेगा बदलाव: नितिन नवीन

पंजाब। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पंजाब के लोगों की बड़ी उम्मीदों को देखते हुए, बीजेपी राज्य में बदलाव की लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पंजाब के अपने पहले दौरे के आखिरी दिन लुधियाना में %युवा मिलनी% कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पंजाब के युवाओं से इस बदलाव में निर्णायक भूमिका निभाने का आग्रह किया। युवा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उन्होंने पंजाब के युवाओं के नज़रिए से वहाँ के मुद्दों को समझा है।

पंजाब के युवाओं की चिंताओं और बीजेपी से उनकी उम्मीदों के बारे में पूछे गए कई सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा किनहम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। आप फ़ैसला करें, और हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। युवाओं ने कई मुद्दों पर सवाल उठाए, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, राज्य पर कर्ज का बोझ, कानून-व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, उद्योगों का पलायन, कृषि संकट, पंजाब से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की कनेक्टिविटी, खेल, स्वास्थ्य सेवा और राज्य में केंद्र सरकार की योजनाओं का सीमित असर शामिल है।विस्तार से जवाब देते हुए नितिन नवीन ने कहा कि किसी भी राज्य या देश की तरक्की के लिए बुनियादी ढाँचे का विकास एक अहम पैमाना है, लेकिन यह कानून-व्यवस्था से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसी तरक्की तभी मुमकिन है जब सरकार की सोच साफ़ हो। उन्होंने कहा कि पंजाब के मौजूदा हालात उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की पुरानी स्थितियों जैसे ही हैं।

प्रमुख समाचार

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में एमवीए का सूपड़ा साफ

मुंबई। महाराष्ट्र विधान परिषद (एमएलसी) चुनावों में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की और राज्य भर में हुई 17 सीटों के चुनाव में से 16 सीटें अपने नाम कीं। इन नतीजों से महाराष्ट्र की राजनीति पर भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की पकड़ और मजबूत हो गई है। वोटिंग से पहले ही महायुति के कई उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके थे, जिससे गठबंधन को काफी बढ़त मिल गई थी। बाकी सीटों पर भी गठबंधन का दबदबा कायम रहा और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के हाथ सिर्फ़ एक सीट लगी।

महायुति को एकमात्र झटका नासिक में लगा, जहाँ भाजपा के बागी उम्मीदवार गोकुल गीते ने गठबंधन समर्थित शिवसेना उम्मीदवार नरेंद्र दराडे को हरा दिया। इस नतीजे को आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महायुति नेतृत्व के लिए एक बड़ी बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि विपक्ष के लिए चुनावी रणनीति को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।

टीएमसी ने बंगाल को लूटकर बर्बाद कर दिया: गिरिराज सिंह

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बंटवारे के बाद कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति की और बाद में राज्य को उसके हाल पर छोड़ दिया। बंटवारे के समय हुई हिंसा का ज़िक्र करते हुए सिंह ने कहा कि उस दौर में बंगाल को बचाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से 1946 के ज़ख्म (डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान हुई हिंसा) बने रहे। सिंह ने पत्रकारों से कहा बंटवारे के समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल को बचाया था। लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद भी 1946 के ज़ख्म यानी डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर हिंदुओं का नरसंहार और उन पर हमले जारी रहे। कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति की और बंगाल को पूरी तरह से उसके हाल पर छोड़ दिया। आखिरकार, टीएमसी ने लूट-पाट करके इसे लगभग बर्बाद ही कर दिया।

निशांत कुमार ही करेंगे जदयू का नेतृत्व : संजय झा

पटना। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) में निशांत कुमार ही नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने सोमवार को बताया कि निशांत कुमार आगे पार्टी का नेतृत्व करेंगे और वही इस पार्टी के भविष्य हैं।पार्टी संगठन को और मजबूत करने तथा उसके विस्तार को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। संजय कुमार झा ने सोमवार को पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके थे। रविवार को राष्ट्रीय परिषद में इसका अनुमोदन किया गया। संजय कुमार झा ने निशांत कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि वह अभी सरकार में काम कर रहे हैं और आगे संगठन में भी काम करेंगे। वहीं बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि निशांत कुमार युवा हैं और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की लगातार मांग थी कि उन्हें पार्टी में शामिल किया जाए और राज्य में काम करने का मौका दिया जाए।

ऑपरेशन कीचड़ से क्या संविधान बदलना चाहती है भाजपा : खेड़ा

नई दिल्ली। कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी चेयरपर्सन पवन खेड़ा ने सोमवार को महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर के तहत दल-बदल की चर्चा को ऑपरेशन कीचड़ करार दिया और शिवसेना (यूबीटी) में हुई बगावत को लेकर भाजपा पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए पवन खेड़ा ने भाजपा के इरादों पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में 240 सीटों पर सिमट जाने के बाद सत्ताधारी पार्टी सांसदों को चुराने का काम कर रही है। खेड़ा ने कहा कि यह ऑपरेशन कीचड़ है क्योंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों में कमल नहीं खिल सका, लेकिन हमारा सवाल यह है कि वे (पीएम नरेंद्र मोदी) इस बात से इतने आहत क्यों हैं कि वे 400 के बजाय 240 सीटों पर ही रुक गए, कि अब वे टीएमसी और शिवसेना जैसी दूसरी पार्टियों से सांसदों को चुराने में लगे हैं? क्यों? इरादा क्या है? क्या असल में संविधान बदलना चाहते हैं? इस डकैती के पीछे क्या मकसद है?

राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री विजय को जन्मदिन की दी बधाई

नईदिल्ली। सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय 52 साल के हो गए। उन्हें सभी राजनीतिक दलों की ओर से जन्मदिन की बधाईयां मिलीं, जिनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल थे। राहुल गांधी ने अभिनेता से राजनेता बने विजय का साथ देने का वादा किया, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी (कांग्रेस) के सबसे नए सहयोगी हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु जोसेफ विजय को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और आपके सभी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। तमिल लोगों के अधिकारों, सम्मान और आकांक्षाओं की रक्षा करने और राज्य की प्रगति के लिए मिलकर काम करने में मैं आपके साथ खड़ा हूं। यह बधाई संदेश विजय द्वारा गांधी को उनके 56वें जन्मदिन पर इसी तरह गर्मजोशी से बधाई देने के ठीक तीन दिन बाद आया है। इससे दोनों नेताओं के बीच बढ़ती सार्वजनिक आत्मीयता का पता चलता है, जबकि पिछले महीने विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तमिलनाडु में गठबंधन की स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। मुख्य विपक्षी पार्टी ष्टरूरू के अध्यक्ष और पूर्व ष्टरूएम.के. स्टालिन ने भी विजय को बधाई दी।

एक लोकतंत्र में दो प्रधानमंत्री के 4399 दिन के राजनीतिक महत्व

सौरभ वार्ष्णेय

10 जून 2026 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक विशेष तिथि के रूप में दर्ज हो गई। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जवाहरलाल नेहरु के 4,398 दिनों के निर्वाचित कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही मोदी स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने।

भारत की राजनीति में कुछ क्षण केवल सांकेतिक नहीं होते, वे इतिहास की दिशा और जनमानस की धारणाओं को भी प्रभावित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार सत्ता में आना और जवाहरलाल नेहरू के लंबे कार्यकाल की बराबरी करना ऐसा ही एक पड़ाव है। यह तुलना केवल वर्षों की संख्या का खेल नहीं है। नेहरू और मोदी दो अलग-अलग युगों, विचारधाराओं और राजनीतिक शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी दोनों की समानता इस बात में है कि उन्होंने अपने-अपने समय में भारतीय राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी और देश की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई।

जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1947 से 1964 तक लगभग 17 वर्षों तक देश का नेतृत्व किया। उनका दौर विभाजन की त्रासदी, संस्थाओं के निर्माण और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का समय था।नेहरू की सबसे बड़ी उपलब्धि यह मानी जाती है कि उन्होंने नवस्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक ढांचे में स्थिर किया। संसदीय व्यवस्था,

स्वतंत्र न्यायपालिका, चुनाव आयोग, वैज्ञानिक संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ उनके दौर की प्रमुख देन हैं। विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता और पंचशील सिद्धांतों ने भारत को वैश्विक मंच पर अलग पहचान दिलाई।हालाँकि नेहरू की नीतियों की आलोचना भी हुई। केंद्रीकृत समाजवादी मॉडल, चीन नीति की विफलता और आर्थिक विकास की धीमी गति उनके आलोचकों के प्रमुख तर्क रहे। फिर भी यह निर्विवाद है कि उन्होंने आधुनिक भारत की बुनियादी संरचना तैयार की।

नरेंद्र मोदी 2014 में राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में उभरे। 2019 में और फिर 2024 में लगातार जीत ने उन्हें भारतीय राजनीति का सबसे प्रभावशाली नेता बना दिया। तीसरे कार्यकाल के साथ उन्होंने नेहरू के लंबे प्रधानमंत्रित्व की बराबरी कर ली है।मोदी का दौर कई मायनों में नेहरू युग से अलग है। जहाँ नेहरू संस्थाओं के निर्माण और वैचारिक बहुलता के प्रतीक थे, वहीं मोदी मजबूत नेतृत्व, केंद्रीकृत निर्णय-प्रक्रिया और राष्ट्रवादी राजनीतिक विमर्श के प्रतिनिधि माने जाते हैं।मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में डिजिटल इंडिया, आधार आधारित कल्याणकारी वितरण, जीएसटी, बुनियादी ढांचे का विस्तार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, स्वच्छ भारत अभियान और वैश्विक मंच पर भारत की सक्रिय उपस्थिति शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन अभियान और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों ने भी उनकी राजनीतिक छवि को मजबूत किया।दूसरी ओर आलोचक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक ध्रुवीकरण और सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण को लेकर सवाल उठाते हैं। बेरोजगारी, कृषि संकट और असमानता जैसे मुद्दे भी लगातार बहस के केंद्र में रहे हैं। इतिहास में किसी नेता का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होता कि वह कितने समय तक सत्ता में रहा। असली प्रश्न यह है कि उसने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को किस दिशा में बदला।

नेहरू ने स्वतंत्र भारत की संस्थागत और वैचारिक नींव रखी। मोदी ने भारतीय राजनीति की शैली और चुनावी संस्कृति को बदल दिया। उन्होंने व्यक्तित्व-आधारित राजनीति, प्रत्यक्ष संचार और राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत चुनावी मशीनरी को नई ऊँचाई दी।

दोनों नेताओं के बीच कुछ रोचक समानताएँ भी हैं-लंबा जनादेश- दोनों को लगातार चुनावी सफलता मिली और जनता ने उन्हें स्थिर नेतृत्व के रूप में स्वीकार किया।राष्ट्रीय स्तर की राजनीति- दोनों ने क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर अखिल भारतीय नेतृत्व स्थापित किया।

व्यक्तित्व का प्रभाव- कांग्रेस में नेहरू और भाजपा में मोदी, दोनों अपनी-अपनी पार्टी की राजनीति के केंद्र रहे।

लेकिन अंतर अधिक गहरे हैं। नेहरू का जोर संस्थागत लोकतंत्र और वैचारिक बहस पर था, जबकि मोदी का मॉडल तेज निर्णय, राजनीतिक केंद्रीकरण और चुनावी दक्षता पर आधारित माना जाता है।

भारतीय लोकतंत्र के लिए इसका क्या अर्थ है? मोदी का नेहरू की बराबरी तक पहुँचना भारतीय लोकतंत्र की एक दिलचस्प विशेषता को भी उजागर करता है—यह व्यवस्था लंबे समय तक लोकप्रिय नेताओं को अवसर देती है, लेकिन अंततः उनका मूल्यांकन जनता ही करती है।

यह पड़ाव भाजपा के लिए राजनीतिक आत्मविश्वास का प्रतीक है। पार्टी इसे कांग्रेस के ऐतिहासिक वर्चस्व के अंत और नए राजनीतिक युग की पुष्टि के रूप में पेश करेगी। वहीं विपक्ष के लिए यह संकेत है कि केवल सत्ता-विरोधी भावना पर्याप्त नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक राष्ट्रीय दृष्टि भी जरूरी है।

52 गांवों के आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव

मूलभूत सुविधाओं की मांग करने पैदल मार्च करते हुए आदवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट

धमतरी। जिले के आदिवासी अंचलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश आखिरकार सोमवार को फूट पड़ा। लगभग 52 गांवों के आदिवासी ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया और कलेक्ट्रेट घेराव के लिए बड़ी संख्या में धमतरी पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पैदल मार्च निकालकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई।ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन और शासन की ओर से केवल आश्वासन ही दिए गए हैं। धरातल पर कोई ठोस काम नहीं होने से लोगों में भारी नाराजगी है।जानकारी के अनुसार, आदिवासी ग्रामीण बड़ी संख्या में वाहनों के माध्यम से धमतरी पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने शोभाराम देवांगन चौक के पास एकत्र होकर कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया। प्रशासन और पुलिस ने उन्हें रोकने तथा समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट घेराव के लिए आगे बढ़ गए।प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं, तो आने वाले दिनों में और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर विकास कार्य दिखाई देने चाहिए।प्रदर्शन में शामिल लोगों की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। अनुमान है कि प्रदर्शन में 500 से लेकर 2000 तक ग्रामीण शामिल है। बड़ी संख्या में आदिवासियों के जुटने को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई।वहीं, प्रदर्शनकारी ग्रामीण कलेक्टर से सीधे मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक जिला प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुनेगा और समाधान का भरोसा नहीं देगा, तब तक वे वापस नहीं लौटेंगे। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों को समझाने और शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, जिससे जिले में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

पाक आईएसआई स्लीपर सेल का सदस्य जांजगीर चांपा से अरेस्ट

सेवक सिंह ने जेएसडब्लू पावर कम्पनी के अलावा बिलासपुर जिले के सीपत में संचालित एनटीपीसी का लोकेशन और वीडियो संदिग्ध नंबरों पर शेयर किया था.

जांजगीर चांपा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के स्लीपर सेल का एक सदस्य अकलतरा से पकड़ा गया है। पकड़ा गया सदस्य अकलतरा में अपनी पहचान छिपाकर किराएदार के रुप में रह रहा था। अकलतरा पुलिस की टीम ने किराएदारों के सत्यापन अभियान के दौरान पंजाब के 23 वर्षीय युवक सेवक सिंह को गिरफ्तार किया है। सेवक सिंह पर खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजने का गंभीर आरोप है।

जांजगीर चांपा पुलिस की जांच में पकड़े गए युवक सेवक सिंह के मोबाइल कॉल डिटेल से संदिग्ध नंबरों पर वीडियो कॉलिंग और वाट्सएप चैट किए गए हैं। वीडियो कॉलिंग और कॉल रिकार्ड के आधार पर युवक के आईएसआई के स्लीपर सेल के सदस्य होने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस ने एटीएस टीम को भी संदिग्ध युवक के पकड़े जाने की जानकारी दे दी है। अकलतरा पुलिस ने बताया कि पंजाब के तरनतारन जिला के पट्टी थाना क्षेत्र का रहने वाला सेवक सिंह पिछले तीन चार महीनों से अकलतरा में रह रहा था। सेवक सिंह क्षेत्र के छत्तीसगढ़ पावर कम्पनी में अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से ठेका श्रमिक के रूप में काम भी कर रहा था। अकलतरा पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया युवक सेवक सिंह अकलतरा के मिनी माता चौक में स्थित राजीव केडिया के मकान में किराएदार था। दरअसल, जिले में बढ़ते अपराध और दूसरे राज्यों से श्रमिकों के आने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने किरायेदारों के सत्यापन के निर्देश दिए थे। जिस पर अकलतरा पुलिस ने सेवक सिंह से मुलाक़ात की और संदिग्ध लगने पर सेवक सिंह का मोबाइल फोन चेक किया।

स्कूल में प्रवेश न मिलने पर छात्र ने की जान देने की कोशिश

जीपीएम। पेंड्रा विकासखंड में छात्र ने निराशा में आकर जान देने की कोशिश की। परिवार वालों का कहना है कि पीड़ित छात्र को नवीं कक्षा में एडमिशन नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो तनाव में है और उसी तनाव की वजह से उसने ये घातक कदम उठाया। छात्रा का इलाज अस्पताल में जारी है। डॉक्टरों ने बताया कि वो खतरे से बाहर है लेकिन उसको डॉक्टरों की विशेष निगरानी में रखा गया है। परिजनों का कहना है कि छात्र ने इस साल आठवीं कक्षा की परीक्षा दी और वो पास भी हो गया। आगे की पढ़ाई के लिए वो कोड़गार हाई स्कूल में प्रवेश लेना चाहता था। छात्र का एडमिशन प्रोसेस चल रहा था लेकिन कोई जरूरी दस्तावेज नहीं होने के चलते छात्र का एडमिशन रुक गया। इस बात का सदमा छात्र को लगा और उसने जान देने की कोशिश की। परिजनों ने बताया कि एडमिशन के लिए जो दस्तावेज बनाने थे उसे बनाने की कोशिश भी की गई लेकिन सफलता नहीं मिली। एडमिशन के लिए एक जरूरी कागज मांगा गया था जिसे बनवाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अफसोस को वहीं कागज नहीं बन पाया। जिस वक्त छात्र ने ये कदम उठाया उस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसकी तबीयत बिगड़ती देखी तब उसने बताया कि उसने जान देने की कोशिश की है। हम इलाज के लिए उसे यहां लेकर आए हैं- पीड़ित छात्र की मां वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी मामले की जानकारी ली जा रही है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि छात्र किस विशेष दस्तावेज के अभाव में प्रवेश नहीं ले पा रहा था और वह दस्तावेज समय पर क्यों उपलब्ध नहीं हो सका। इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था में दस्तावेज संबंधी प्रक्रियाओं और विद्यार्थियों पर बढ़ते मानसिक दबाव को लेकर चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि स्कूल प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया जाए तथा विद्यार्थियों की नियमित काउंसलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में किसी छात्र को ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े।

जलकैना देव स्थल को मुक्त कराने की मांग तेज, बालोद में आदिवासियों का 'जातरा

बालोद। जलकैना देव स्थल को लेकर आदिवासी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आदिवासी समाज का कहना है कि उनका पारंपरिक देव स्थल वर्षों से विवाद में है और प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस बीच डोंडीलोहारा के लोहारा ब्लॉक में 20 जून को हजारों आदिवासी एक बड़े 'जातरा' में शामिल हुए। यह आयोजन जलकैना देव स्थल को मुक्त कराने और अपनी संस्कृति व आस्था की रक्षा के लिए किया गया। लेकिन इस दौरान एक ऐसा मंजर भी आया जब देवस्थल जा रहे सामाजिक जातरा से सेवा अर्जी का सामान प्रशासन ने छीन लिया, जिसे लेकर जमकर झड़प भी हुई। सर्व आदिवासी समाज का आरोप है कि बाबा बालक दास के आश्रम ने संरक्षित वन भूमि पर कब्जा कर लिया है। समाज का कहना है कि उनके पारंपरिक जलकैना देव स्थल को आश्रम की चारदीवारी के भीतर कर दिया गया है, जिससे आदिवासी अपने धार्मिक अनुष्ठान स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहे हैं। कई महीनों तक प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं निकलने पर समाज ने अपनी परंपरा के अनुसार 'जातरा' आयोजित करने का फैसला किया। 20 जून की सुबह तुएगोंदी के जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि पुलिस आश्रम की सुरक्षा के लिए तैनात थी। आदिवासी समाज का यह भी आरोप है कि कुछ पत्रकारों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोका गया। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि जब वे पारंपरिक पूजा सामग्री और 'सेवा अर्जी' लेकर जलकैना देव स्थल की ओर जा रहे थे, तब प्रशासन और पुलिस ने उनकी सामग्री जब्त कर ली। इस घटना के बाद कुछ युवाओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। हालांकि, समाज के बुजुर्गों और पदाधिकारियों ने स्थिति को संभाला और माहौल को शांत किया।

पेट्रोल और डीजल की किल्लत पर बीजापुर में भड़के किसान

बीजापुर। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में डीजल और पेट्रोल की कमी को लेकर किसानों का गुस्सा सामने आया है। किसानों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए बताया है कि ईंधन की किल्लत से खेती किसानी का काम प्रभावित हो रहा है। इस वजह से किसानों ने एक दिवसीय ट्रैक्टर रैली निकाली है। किसानों ने बीजापुर के नैमेड में ट्रैक्टर के जरिए विरोध प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में किसान अपने-अपने ट्रैक्टरों के साथ नैमेड पहुंचने लगे। किसानों ने ट्रैक्टर के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि समय पर डीजल और पेट्रोल नहीं मिलने के कारण खेतों की जुताई, सिंचाई और अन्य जरूरी कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इससे न सिर्फ फसल उत्पादन पर असर पड़ रहा है, बल्कि किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार और जिला प्रशासन से जल्द इस समस्या का हल निकालने की मांग की है। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी के नेतृत्व में किसानों ने नैमेड से बीजापुर तक ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली के दौरान किसानों ने नैमेड स्थित रेड्डी पेट्रोल पंप का घेराव किया। इसके बाद बीजापुर पहुंचकर जीवीआर, लुंकड़ और पवार पेट्रोल पंप (गंगालर रोड) पर भी प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जताई। रैली के बाद नया बस स्टैंड बीजापुर में एक आमसभा आयोजित की गई, जिसमें किसानों ने अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा और प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही ईंधन की आपूर्ति सुचारू नहीं की गई, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

नया सत्र शुरू होने के बाद भी स्कूल भवन का निर्माण अधूरा

कांकेर। कई प्रयासों के बाद भी जिले में शिक्षा की स्थिति दयनीय है। कहीं जर्जर भवन में स्कूले लग रहा है, तो कहीं भवन ही नहीं है। ऐसा ही मामला जिला मुख्यालय से महज 23 किमी दूर बाबूदबेना गांव का है। जहां प्राथमिक स्कूल भवन अत्यधिक जर्जर होने के कारण वर्तमान में स्कूल गांव के एक ग्रामीण के घर में पिछले सत्र से स्कूल संचालित हो रहा है। स्कूल ही नहीं ग्रामीण का घर मध्याह्न भोजन बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। शिक्षकों का ऑफिस भी उसी घर में संचालित हो रहा है। बेहतर शिक्षा के लिए सरकार स्कूल चलो अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, मध्याह्न भोजन जैसी अनेक योजनाएं और अभियान चला रही है। लेकिन अभी भी कई स्कूलों का बुरा हाल है। शिक्षक बताते हैं कि भवन जर्जर हो गया है। बच्चे एक साल से रंगमंच में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन बरसात में दिक्कत हो रही थी। इस पर गांव के एक ग्रामीण ने पहल करते हुए अपने खाली पक्के मकान को स्कूल संचालित करने दे दिया। अभी वर्तमान में नए भवन की स्वीकृति मिलने के बाद स्कूल बनना शुरू हो गया है। लेकिन वह कब पूरा होगा पता नहीं, तब तक बच्चों को इसी ग्रामीण के घर में बैठकर पढ़ना होगा। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में स्कूल का निर्माण बारिश के मौसम में लेटलतीफी के साथ शुरू किया गया। इसका असर स्कूल की दर्ज संख्या में भी देखने को मिल रहा है। अभिभावक इस स्कूल से अपने बच्चों का नाम कटा कर टीसी निकलवा कर दूसरे स्कूल में दाखिला करवाने मजबूर हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

किसान रेवती राम ने अपनाई नैनो उर्वरक आधारित खेती'

कोरिया। मुख्यमंत्री देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन किसानों को आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कृषि को अधिक लाभकारी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किसानों को समय पर खाद-बीज, उन्नत कृषि आदान तथा नई तकनीकों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव अब किसानों की खेती में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कोरिया जिले के ग्राम अमरपुर निवासी किसान रेवती राम राजवाड़े ने आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने में रूचि दिखाई है। किसान रेवती राम अपने पुत्र खिलेंद्र राजवाड़े के साथ लगभग 18 एकड़ कृषि भूमि में मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं। रेवती राम बताते हैं कि अच्छी फसल के लिए केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही समय पर सही तकनीक और उर्वरकों का उपयोग भी जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी फसलों में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का उपयोग करने जा रहे हैं।

चेन्नई में फंसी छत्तीसगढ़ की युवतियों ने विधायक लगाई गुहार

सरगुजा। जिले के सीतापुर क्षेत्र की तीन युवतियों के चेन्नई में फंसने का मामला सामने आया है। युवतियों ने घर वापस लौटने के लिए सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो से मदद की गुहार लगाई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद विधायक ने पुलिस प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेने और युवतियों को सुरक्षित वापस लाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम भरतपुर, बेलजोरा और बिनई की रहने वाली तीन युवतियों को जशपुर में करीब तीन महीने तक सिलाई का प्रशिक्षण दिया था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बेहतर रोजगार और प्लेसमेंट का झांसा देकर उन्हें चेन्नई के कांचीपुरम ले जाया गया। अब जब युवतियां अपने घर लौटना चाहती हैं तो उनसे 10-10 हजार रुपये की मांग की जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना मुश्किल हो रहा है। परेशान युवतियों ने चेन्नई से ही सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो से मोबाइल से संपर्क कर पूरी आपबीती बताई और सुरक्षित घर वापस लाने की अपील की।

ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा एक्शन

दुर्ग। ऑनलाइन जुआ सट्टा और म्यूल अकाउंट नेटवर्क के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में तीन अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना खुर्सीपार पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने आरोपियों के कब्जे से 81 एटीएम कार्ड, 62 बैंक पासबुक, 5 चेकबुक, 13 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड, एक लैपटॉप और हार्ड डिस्क समेत करीब ढाई लाख रुपए की सामग्री जब्त की है। वहीं एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि खुर्सीपार के आईटीआई खेल मैदान के पास कुछ युवक डिजिटल उपकरणों के माध्यम से ऑनलाइन सट्टे का संचालन कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को मौके से पकड़ लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आईपीएल सीजन के दौरान आरोपी रांची, झारखंड से इस पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहे थे। आरोपियों के खिलाफ खुर्सीपार थाने में धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

जपं कार्यालय में तालाबंदी कर जनप्रतिनिधियों ने किया प्रदर्शन

भानुप्रतापपुर। कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल जनपद पंचायत में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब जनपद अध्यक्ष गोपी बघाई के नेतृत्व में जनपद सदस्यों और सरपंचों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जनप्रतिनिधियों ने जनपद पंचायत कार्यालय में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सीईओ द्वारा सरपंचों को परेशान किया जा रहा है तथा विकास कार्यों में कमीशनखोरी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दुर्गूकोंदल जनपद पंचायत के जनपद अध्यक्ष गोपी बघाई के नेतृत्व में जनपद सदस्य और सरपंच आज जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यालय में तालाबंदी कर दी और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि जनपद पंचायत के सीईओ विकास कार्यों में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं।

एकाकी जीवन में उर्मिला को मिला सुरक्षित आशियाने का संबल

कोरिया। समय पर मिली छोटी-सी मदद किसी जरूरतमंद के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। ऐसा ही बदलाव कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत फूलपुर निवासी श्रीमती उर्मिला के जीवन में देखने को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मिले पक्के मकान ने उनके एकाकी जीवन को नई सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास प्रदान किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विवाह के कुछ समय बाद ही श्रीमती उर्मिला का वैवाहिक जीवन टूट गया। इसके बाद उनके सामने आजीविका और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती खड़ी हो गई। विपरीत परिस्थितियों के बीच उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत पूजा महिला स्व-सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें गांव के विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बनाने का कार्य मिला। इसी आय के माध्यम से वह अपने जीवन-यापन की जिम्मेदारी निभा रही हैं।

स्कूलों में मंत्रजाप का मुस्लिम विकास मंच का विरोध

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में छात्रों से मंत्रजाप करवाने की अनिवार्यता को लेकर विरोध जारी है। इस फैसले को लेकर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मुस्लिम विकास मंच के अध्यक्ष असद सिद्दीकी की अगुवाई में समाज ने विरोध जताते हुए आज मौन रैली निकाली। इस दौरान लोग हाथों में 'तुगलकी फरमान वापस लो' जैसी लिखी तख्तियां पकड़े नजर आए। कलेक्टर कार्यालयल पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल के नाम से सौंपा, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई। दरअसल, छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने 12 जून 2026 को एक आदेश जारी कर नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से राज्य के सभी शासकीय स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान सरस्वती वंदना और विभिन्न मंत्रों के जाप (जैसे भोजन मंत्र, गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र) को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इस आदेश का मुस्लिम समाज ने विरोध करते हुए इसे ﷺतुगलकी फरमानﷺ करार दिया है। समाज का कहना है कि मंत्र जाप को तीन चरणों में लागू करने की तैयारी की जा रही है, जो संविधान की भावना के विपरीत है। मुस्लिम समाज का तर्क है कि यह निर्णय नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता है। उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म और इबादत का तरीका होता है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 28(1) स्पष्ट रूप से कहता है कि सरकारी या राज्य से वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। समाज का आरोप है कि किसी एक धर्म से जुड़े मंत्रों और प्रार्थनाओं को सभी छात्रों के लिए अनिवार्य करना इन संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है।मुस्लिम समाज ने समानता के अधिकार का भी मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि इस तरह की अनिवार्यता से अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों में भेदभाव की भावना उत्पन्न हो सकती है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ज्ञापन में समाज ने वर्ष 2002 के Aruna Roy vs Union of India मामले का भी हवाला दिया है, जिसमें सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी विशेष धर्म की उपासना या धार्मिक अनुष्ठान को बढ़ावा देने को अनुचित बताया गया था। मुस्लिम समाज ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। संगठन के अध्यक्ष ?असद सिद्दीकी ने स्पष्ट किया कि इस आदेश के विरोध में उनका पहला कदम मौन जुलूस और शांतिपूर्ण धरना देना था।

संदिग्ध सामान तोड़ने के दौरान धमाका

धमाके में घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. युवक के हाथ और चेहरे पर गंभीर चोट आए हैं.

जीपीएम। मरवाही थाना इलाके के ग्राम टिकठी में संदिग्ध सामान को तोड़ने के दौरान उसमें धमाका हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक 19 साल का युवक कृष्ण कुमार चंद्र गांव की गली से होकर जा रहा था। तभी गली में उसे एक संदिग्ध सामान पड़ा हुआ नजर आया।

युवक कृष्ण कुमार चंद्र उस सामान को लेकर अपनी बाड़ी में पहुंचा। युवक के परिजनों ने बताया कि जो संदिग्ध सामान था उसकी लंबाई तीन इंच और 1 इंच की गोलाई वाला था। युवक ने सामान को कुदाल की मदद से खोलकर देखने की कोशिश की, इसी दौरान उसमें धमाका हो गया।

धमाके की आवाज सुनते ही घर और गांव के लोग मौके पर पहुंचे, वहां देखा तो पाया कि युवक गंभीर रुप से जख्मी होकर जमीन पर गिरा पड़ा है। आनन-फानन में उसे गंभीर हालत में लेकर लोग अस्पताल पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। युवक का फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज जारी है।

घटना के बाद गांव में भय और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के बीच इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर वह क्या चीज थी, जिसपर चोट करते ही विस्फोट हो गया। पुलिस को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। प्रारंभिक तौर पर मामले की जांच की जा रही है। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात, संदिग्ध या विस्फोटक जैसी दिखने वाली वस्तु को हाथ न लगाएं और इसकी सूचना तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल रमेन डेका से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने की भेंट

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से सोमवार

को यहां लोकभवन में रायपुर दक्षिण विधायक श्री सुनील सोनी, उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, रायपुर ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू एवं रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने सौजन्य भेंट की।

रायपुर की बेटी आईएएस श्रद्धा शुक्ला का कैडर बदला, अब मध्यप्रदेश में देंगी सेवा

रायपुर। रायपुर की बेटी 2022 बैच की

आईएएस अधिकारी श्रद्धा शुक्ला का कैडर बदलकर मध्यप्रदेश कर दिया गया है। इससे पहले वह तेलंगाना कैडर में पदस्थ थीं। विवाह के बाद केंद्र सरकार की कॉमन कैडर नीति के तहत उन्होंने अपने पति के साथ मध्यप्रदेश में सेवाएं देने का विकल्प चुना। आईएएस श्रद्धा शुक्ला कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की पुत्री हैं। कुछ माह पहले उनका विवाह मध्यप्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी ऐश्वर्या वर्मा से हुआ था। विवाह के बाद दंपती को एक ही राज्य में सेवाएं देने का अवसर मिले, इसके लिए लागू कॉमन कैडर व्यवस्था के तहत श्रद्धा शुक्ला ने मध्यप्रदेश कैडर का विकल्प चुना। इसके बाद उनका कैडर तेलंगाना से बदलकर मध्यप्रदेश आवंटित कर दिया गया। श्रद्धा शुक्ला के मध्यप्रदेश कैडर में स्थानांतरण को लेकर रायपुर और प्रशासनिक हलकों में चर्चा है। इसे अखिल भारतीय सेवाओं में लागू उस व्यवस्था का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत पति-पत्नी दोनों अधिकारियों को यथासंभव एक ही राज्य में पदस्थापना देने का प्रयास किया जाता है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नवीनीकरण शुरू 30 जून तक करें ऑनलाइन आवेदन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सत्र 2026-27 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने पात्र विद्यार्थियों से 30 जून 2026 तक आवेदन करने की अपील की है। विभाग के अनुसार, नवीनीकरण के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल 20 जून से खुल चुका है और आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है। वहीं, नए विद्यार्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2026 से शुरू होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण-पत्र तथा अध्ययनरत पाठ्यक्रम के पिछले वर्ष की परीक्षा का परिणाम संलग्न करना अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से आधार-आधारित प्रणाली से सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में किया जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक खाता सक्रिय हो तथा आधार से लिंक हो।

24 की ग्राम सभा बनेगी लाखों ग्रामीणों के पक्के आवास के सपनों की आधारशिला

रायपुर। सरगुजा जिले में 24 जून को

आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाएं ग्रामीण विकास, जनभागीदारी और पारदर्शी सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित इन ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से तैयार अंतिम प्राथमिकता सूची पर निर्णय लिया जाएगा। यह प्रक्रिया उन हजारों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष महत्व रखती है, जो लंबे समय से अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं। ग्राम सभाओं में ग्रामीणों की सहभागिता से पात्र हितग्राहियों का चयन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के तहत सरगुजा जिले में कुल 1 लाख 16 हजार 36 परिवारों का सर्वे किया गया है। इनमें अम्बिकापुर विकासखंड के 30 हजार 163, बतौली के 10 हजार 529, लखनपुर के 19 हजार 89, लुण्ड्रा के 18 हजार 825, मैनपाट के 11 हजार 765, सीतापुर के 13 हजार 892 तथा उदयपुर के 11 हजार 773 परिवार शामिल हैं। सर्वेक्षण के आधार पर तैयार सूची को ग्राम सभा में सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जाएगा। इसका उद्देश्य पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।

सोमनाथ मंदिर हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान और आस्था का प्रमुख केन्द्र: साय

छत्तीसगढ़ से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए 1000 से अधिक विशिष्टजन, पद्मश्री, कलाकार एवं साहित्यकार हुए रवाना

■ मुख्यमंत्री ने विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का किया शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को यहां राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सोमनाथ मंदिर हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रमुख केन्द्र है। सोमनाथ मंदिर को अनेक बार आक्रांताओं ने तोड़ा, लेकिन हर बार मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, ये देशवासियों की अटूट आस्था का परिणाम है।

सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत विशेष ट्रेन से छत्तीसगढ़ से सोमनाथ के लिए 1000 से अधिक विशिष्टजन, पद्मश्री, राज्य एवं राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कलाकार एवं साहित्यकार रवाना हुए। यात्रा में शामिल श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के शिवालयों की पावन भूमि के माटी कलश और पावन नदियों का जल कलश बाबा सोमनाथ को अर्पण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने भगवान सोमनाथ से छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरवशाली दिन है जब प्रदेश भर से 1000 से अधिक श्रद्धालु भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में 11 जनवरी 2026 से 11 जनवरी 2027 तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व राष्ट्रीय स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस पर्व के अंतर्गत सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, उन्होंने भारत की आजादी के बाद राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक के रूप में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। 75 वर्ष पूर्व देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद जी ने पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ से पद्मश्री, राज्य एवं राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कलाकार एवं साहित्यकार इस यात्रा में अपने साथ अपने-अपने क्षेत्रों के धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के शिवालयों की पावन माटी और पावन नदियों कें जल कलश लेकर रवाना हो रहे हैं। यह यात्रा भारत की सांस्कृतिक एकता का जीवंत उदाहरण है।

इस अवसर पर संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि सोमनाथ धाम की यह यात्रा श्रद्धालुओं को केवल आध्यात्मिक अनुभूति ही नहीं बल्कि भारत की महान सांस्कृतिक परम्परा और राष्ट्रीय गौरव को निकट से अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करेगी। भगवान सोमनाथ से प्रार्थना है कि वे हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित भारतवर्ष को समृद्धि, शांति और विकास के पथ पर अग्रसर करें। मुख्यमंत्री श्री साय ने सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उनकी मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए उन्हें अंगवस्त्र भेंट किया। इस अवसर पर कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री अनुज शर्मा, श्री इंद्रकुमार साहू, श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा, श्री संपत अग्रवाल, फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन सहित जनप्रतिनिधिगण एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

प्रदेश का सबसे मॉडल शहर बनेगा रायगढ़ : वित्त मंत्री

■ शहर में चल रहे प्रमुख विकास कार्यों का किया निरीक्षण, गुणवत्ता और समय-सीमा पर दिया विशेष जोर

रायपुर। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी ने सोमवार को रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में संचालित विभिन्न महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मरीन ड्राइव, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड (आईएसबीटी), एफसीआई ऑक्सीजोन, मिट्ठुमुड़ा तालाब, किसान राइस मिल ऑक्सीजोन तथा कयाघाट पुल सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थल पर पहुंचकर अवलोकन किया और अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि रायगढ़ को प्रदेश के सबसे आधुनिक, सुव्यवस्थित और सुविधासंपन्न शहर के रूप में विकसित करना उनका संकल्प है। उन्होंने कहा कि सड़क, परिवहन, पर्यावरण, जल संरक्षण और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी ये परियोजनाएं पूर्ण होने के बाद रायगढ़ विकास का नया मॉडल बनकर उभरेगा।

प्रगति नगर स्थित निर्माणाधीन मरीन ड्राइव का निरीक्षण करते हुए वित्त मंत्री ने कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने मुख्य बॉक्स कल्वर्ट एवं डायवर्सन निर्माण कार्य समय पर पूरा होने पर संतोष व्यक्त किया और संबंधित एजेंसियों की सराहना की।उन्होंने कहा कि मरीन ड्राइव केवल यातायात सुविधा का माध्यम नहीं, बल्कि रायगढ़ की नई पहचान बनने जा रही है। इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी, यातायात व्यवस्था सुगम होगी तथा नागरिकों को एक आकर्षक सार्वजनिक स्थल भी मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को आगामी नवंबर तक परियोजना पूर्ण करने के निर्देश दिए।

वित्त मंत्री ने निर्माणाधीन अंतर्राज्यीय बस स्टैंड (आईएसबीटी) का निरीक्षण करते हुए कहा कि यह परियोजना आगामी चार दशकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की जा रही है। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड में एक साथ 30 बसों के संचालन की सुविधा होगी, जबकि अतिरिक्त 40 बसों के लिए भी पर्याप्त पार्किंग एवं स्थान आरक्षित रहेगा।

यात्रियों के लिए आधुनिक प्रतीक्षालय विकसित किया जा रहा है, जहां लगभग 550 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। वहीं बसों के रखरखाव और मरम्मत के लिए पृथक वर्कशॉप क्षेत्र भी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बस टर्मिनल रायगढ़ को प्रदेश और देश के प्रमुख शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा तथा यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री ने एफसीआई परिसर में विकसित किए जा रहे ऑक्सीजोन प्रोजेक्ट का भी अवलोकन किया। लगभग सात एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहे इस हरित परिसर को उन्होंने रायगढ़ के पर्यावरणीय भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने अधिकारियों को नागरिकों की सुविधा के लिए ऑक्सीजोन में दो प्रवेश द्वार विकसित करने के निर्देश दिए। श्री चौधरी ने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दौर में ऐसे हरित क्षेत्रों का विकास समय की आवश्यकता है। यह परियोजना शहरवासियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

श्री चौधरी ने कहा कि रायगढ़ में विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को समान प्राथमिकता दी जा रही है। यही कारण है कि शहर में आधुनिक आधारभूत संरचना के साथ-साथ हरित परियोजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अवसर पर नगर निगम महापौर श्री जीवर्धन चौहान, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के लिए रायगढ़ से 17 श्रद्धालु रवाना

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की तीर्थ यात्रा योजना के तहत रायगढ़ जिले के 17 श्रद्धालु सोमवार को सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के लिए रवाना हुए। प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी ने यात्रियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनकी सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा की कामना की। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों एवं श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए उन्हें देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन का अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा योजना केवल यात्रा नहीं, बल्कि लोगों की वर्षों पुरानी धार्मिक आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बन रही है।

सोमनाथ धाम के दर्शन के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक एवं अन्य कारणों से कई लोगों के लिए देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता, लेकिन इस योजना ने उन्हें पवित्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन का अवसर प्रदान किया है। श्रद्धालुओं ने इसे अपने जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ-साथ संस्कृति, परंपरा और धार्मिक आस्था के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। तीर्थ यात्रा जैसी योजनाएं समाज के उन वर्गों तक भी धार्मिक अवसर पहुंचा रही हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में ऐसे तीर्थ स्थलों की यात्रा नहीं कर पाते।

पहली बारिश ने खोली निगम की पोल

■ राजधानी के कई इलाकों में जलभराव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं नगरी निकाय मंत्री अरुण साव के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद महापौर मीनल चौबे और नगर निगम अधिकारियों ने बरसात पूर्व तैयारियों को लेकर पूरी तरह अनदेखी की है। पहली बारिश के साथ ही शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है।

पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड नंबर 34 नूरानी चौक, राजातालाब, अरमान नाला में लगातार जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने आरोप लगाया कि उन्होंने दो माह पहले ही जोन क्रमांक 4 की समीक्षा बैठक में जलभराव की आशंका जताई थी और नाले की मैनुअल सफाई कराने का सुझाव दिया था, लेकिन जोन कमिश्नर दिव्या चंद्रवंशी और अन्य अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया।

आकाश तिवारी ने बताया कि विगत चार वर्षों से गोविंद नगर-रविनगर से ऑक्सीजन होते हुए नूरानी चौक जाने वाले नाले की नियमित मैनुअल सफाई होती रही, जिसके कारण वार्ड में जलभराव नहीं होता था। इस वर्ष सफाई नहीं कराई गई, जिसके चलते बरसात शुरू होने से पहले ही इलाका जलमग्न हो गया है। उन्होंने कहा, बरसात के पूर्व तैयारी कागजों में ही सिमट कर रह गई है। न मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन हुआ, न महापौर के।

नेता प्रतिपक्ष ने नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा को भी लिखित रूप से वार्ड की स्थिति से अवगत कराया था, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तिवारी ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते नाले की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाली पूर्ण बरसात में स्थिति और भयावह हो सकती है। स्थानीय लोगों ने भी नगर निगम प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि दावों के विपरीत जमीनी हकीकत पूरी तरह अलग है। जगह-जगह पानी भरा होने से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है।

मुख्य सचिव ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने सोमवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के समस्त विभागों के भार सादक सचिवों की बैठक ली। बैठक में विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव सभी ऑनलाइन सेवाओं को सेवा सेतु में लाने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। मुख्य सचिव ने आगामी 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के लिए विभागों के अंतर्गत सभी जरूरी तैयारियों के साथ विभागीय अधिकारियों को विधानसभा में उपस्थित रहने के निर्देश दिए है।

मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों को वरीयता देने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मानिटरिंग करने के निर्देश दिए है। बैठक में ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डेसबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, डी रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, मनरेगा, पीएम सूर्य घर बिजली सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को विभागों के अंतर्गत रिक्त पदों की सूची अद्यतन करने एवं कर्मचारी चयन मंडल के कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से ली।

बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमख सचिव श्रीमती शहला निगार, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, मुख्यमंत्री एवं सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत, गृह विभाग की सचिव श्रीमती नेहा चम्पावत, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस.प्रकाश, सामान्य प्रशासन, जनशिकायत निवारण एवं उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उभोक्ता संरक्षण एवं वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव सुश्री आर.शंगीता, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) सचिव श्री भुवनेश यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के सचिव मौजूद थे।

रायपुर कमिश्नरेट में 12 घंटे के भीतर अलग-अलग स्थानों पर मिले 3 युवकों के शव

रायपुर। राजधानी रायपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में पिछले 12 घंटों के भीतर तीन अलग-अलग स्थानों पर शव मिलने से सनसनी फैल गई है। खमतराई थाना और पुरानी बस्ती थाना क्षेत्रों में सामने आए इन मामलों ने पुलिस प्रशासन को भी सतर्क कर दिया है। शुरुआती जांच में सभी मामलों में हत्या की आशंका जताई जा रही है।

खमतराई थाना क्षेत्र स्थित डब्ल्यूआरएस कॉलोनी के एक खुले मैदान में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात एक अज्ञात युवक का शव खून से लथपथ हालत में मिला। स्थानीय लोगों ने जब शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची खमतराई पुलिस ने पाया कि युवक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान हैं और काफी मात्रा में खून फैला हुआ है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या भारी पत्थर से सिर पर वार कर की गई है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव की पहचान के लिए आसपास के थानों में गुमशुदगी के मामलों की जानकारी खंगालनी शुरू कर दी है। जांच के दौरान युवक के दाहिने हाथ पर आरके सारथी लिखा का टैटू मिला है।

खमतराई थाना क्षेत्र के ही मेटल पार्क इलाके में एक और अज्ञात युवक का शव मिला है, जो लगभग चार से पांच दिन पुराना बताया जा रहा है। शव अत्यधिक सड़-गल चुकी हालत में मिला, जिससे इसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। इस शव के शरीर पर चांदनी नाम का टैटू भी पाया गया है। पुलिस इसे भी हत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। आसपास के गांवों और क्षेत्र में गुम इंसान की रिपोर्टों के आधार पर पहचान की कोशिश जारी है।

तीसरा मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के अंतर्गत भाठागांव इलाके में रिंग रोड किनारे सामने आया है, जहां एक शव मिलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। लगातार तीन शव मिलने की घटनाओं के बाद रायपुर पुलिस ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है। शुरुआती तौर पर सभी मामलों में हत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि शवों की पहचान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री दंतेवाड़ा में झमाझम बारिश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आखिरकार दस्तक दे दी है।मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने दंतेवाड़ा जिले से मानसून के प्रवेश की आधिकारिक पुष्टि की है।इसके साथ ही प्रदेशभर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है।अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 22 जून को दक्षिण-पश्चिम मानसून ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में प्रवेश कर लिया है।मानसून की उत्तरी सीमा वर्तमान में दंतेवाड़ा सहित देश के कई हिस्सों से होकर गुजर रही है, जो इसके लगातार आगे बढ़ने का संकेत दे रही है।

अगले 48 घंटों में बदलेगा मौसम का मिजाजमौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। बस्तर संभाग के साथ-साथ मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गरज-चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश भी दर्ज की जा सकती है।

गर्मी और उमस से मिलेगी राहतपिछले कई दिनों से तेज धूप, गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए मानसून की एंट्री राहतभरी खबर लेकर आई है। बारिश की शुरुआत के साथ तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे मौसम सुहावना होगा।किसानों के लिए खुशखबरीमानसून का आगमन किसानों के लिए भी राहत लेकर आया है। खरीफ सीजन की बुवाई का इंतजार कर रहे किसानों को अब पर्याप्त बारिश मिलने की उम्मीद है, जिससे खेती-किसानी की गतिविधियां रफ्तार पकड़ सकेंगी।अब पूरे प्रदेश पर रहेगी नजरदंतेवाड़ा से प्रवेश करने के बाद मानसून धीरे-धीरे पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय होगा। मौसम विभाग लगातार इसकी निगरानी कर रहा है और आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है

दो दल, दो खलनायक, क्या अभिषेक ने तोड़ी टीएमसी

राकेश कुमार

जब लंका जलती है, तो लोग अक्सर उस विभीषण को ढूंढते हैं जिसने घर का भेद दिया। राजनीति में भी जब कोई बड़ी पार्टी अचानक ताश के पत्तों की तरह ढहती है, तो जनता सबसे पहले एक %विलेन% की तलाश करती है। इस वक्त पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में भी यही हो रहा है। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उद्धव ठाकरे के सिपहसालार संजय राउत ही अपनी-अपनी पार्टियों को इस हाल में पहुंचाने के असली जिम्मेदार हैं? हालांकि, राजनीति इतनी सीधी नहीं होती। इस टूट के पीछे अंदरूनी कमजोरी, पुरानी नाराजगी और बाहरी दबाव का एक पूरा चक्रव्यूह काम कर रहा है। आइए, इसे बेहद आसान भाषा में समझते हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन जून 2026 में हुआ यह विद्रोह उनके इतिहास की सबसे बड़ी संगठनात्मक हार है। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 58 विधायक और 20 लोकसभा सांसद एक साथ बागी हो गए। हैरान करने वाली बात यह है कि इन बागियों का गुस्सा ममता बनर्जी पर नहीं, बल्कि उनके भतीजे और पार्टी के नंबर दो नेता अभिषेक बनर्जी पर फूटा है।बागी नेताओं का सीधा आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने पूरी पार्टी को आई-पैक नाम की एक कॉर्पोरेट चुनावी एजेंसी के हवाले कर दिया था। जो नेता वर्षों से जमीन पर लाठियां खाकर पार्टी को सत्ता में लाए थे, उन्हें अचानक एक प्राइवेट कंपनी के अफसरों के इशारों पर चलना पड़ रहा था। टिकट बांटने से लेकर संगठन के हर छोटे-बड़े फैसले में पुराने नेताओं को दरकिनार किया गया, जिससे उनका स्वाभिमान आहत हुआ। बागी नेता खुलकर कह रहे हैं कि वे ममता दीदी का सम्मान करते हैं, लेकिन अभिषेक का कॉर्पोरेट नेतृत्व उन्हें स्वीकार नहीं है। इस गुस्से को हवा देने का काम किया 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव ने, जहां भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में टीएमसी को करारी शिकस्त दी। इस हार ने पार्टी के भीतर अभिषेक की रणनीतियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। रही-सही कसर कोयला और शिक्षक भर्ती जैसे घोटालों में ईडी और सीबीआई की बढ़ती जांच ने पूरी कर दी। महाराष्ट्र की कहानी भी बंगाल से अलग नहीं है। साल 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद जून 2026 में उद्धव ठाकरे को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा है। इस बार उनके बचे हुए नौ लोकसभा सांसदों में से छह सांसद बागी होकर शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। यह बगावत पूरी कानूनी गणित के साथ की गई है, क्योंकि ठीक दो-तिहाई (66.6%) सांसद टूटने की वजह से दलबदल कानून के तहत इनकी सांसदी सुरक्षित रहेगी। इन बागी सांसदों का सीधा निशाना संजय राउत की कार्यशैली और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर है। नेताओं का आरोप है कि संजय राउत जैसे गिने-चुने चेहरों के अत्यधिक प्रभाव के कारण उद्धव ठाकरे से मिलना आम कार्यकर्ताओं और सांसदों के लिए नामुमकिन हो चुका था। जमीन का सच ठाकरे परिवार तक पहुंचने ही नहीं दिया गया और टिकटों का बंटवारा बंद कमरों में मनमाने ढंग से हुआ। दूसरा बड़ा कारण विचारधारा का भ्रम रहा। कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में रहने के कारण शिवसेना-यूबीटी के सांसद अपने ही क्षेत्रों में घिर रहे थे, क्योंकि उनका पारंपरिक वोटर प्रखर हिंदुत्ववादी है। सांसदों को लगा कि अगर वे इसी गठबंधन में रहे, तो उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके अलावा, सत्ताधारी महायुति सरकार ने विपक्षी सांसदों के इलाकों में विकास फंड रोक दिए थे। अपने क्षेत्र में काम न करा पाने और फंड की किल्लत के कारण सांसदों ने सत्ता पक्ष के साथ जाना बेहतर समझा।

विचारधारा से कायम रहती है दलों की एकजुटता

शेखर गुप्ता

व्यापक दलबदल के इस दौर में जब सभी दलबदल करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर रुख कर रहे हैं तब तीन ऐसे राजनीतिक प्रश्न उठते हैं जो आपस में संबद्ध हैं। राजनीतिक दल क्यों टूटते हैं? लोग दलबदल क्यों करते हैं? क्या विचारधारा, सिद्धांत और यहां तक कि निष्ठा की कोई अहमियत है?

इन प्रश्नों के साथ एक बुनियादी तार्किक सवाल पैदा होता है। आखिर क्यों कुछ दल टूट जाते हैं या बुरी तरह छिन्न-भिन्न हो जाते हैं जबकि अन्य दल नहीं टूटते। हाल के दिनों की बात करें तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का पतन या कहें भीतर से हुई बगावत सबसे बड़ी सुर्खी रही है। लेकिन यहां भी प्रतिस्पर्धा है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना (यूबीटी) का शेष हिस्सा फिर से टूट रहा है। झारखंड में 'इंडिया' गठबंधन के विधायकों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) समर्थित निर्दलीय राज्य सभा उम्मीदवार परिमल नाथवानी के लिए क्रॉसवोट किया। कांग्रेस को कुछ सांत्वना डीके शिवकुमार से मिल सकती है जिन्होंने कर्नाटक के एमएलसी चुनाव में राजग से कुछ को क्रॉसवोट कराया।

आम आदमी पार्टी पहले ही सात सांसद खो चुकी है। बीजू जनता दल ने तीन सांसदों को भाजपा/राजग की झोली में डाला है। हाल ही में वाईएस जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी (युवजन श्रमिक रैयतु कांग्रेस पार्टी) ने भी सदस्य गंवाए हैं और सभी राजग (अर्थात भाजपा) की संख्या से जुड़ गए। शिरोमणि अकाली दल, अपनी धार्मिक एकता और विशिष्ट विचारधारा के बावजूद सदस्यों को बाहर जाने से नहीं रोक पा रहा। इनमें मनप्रीत सिंह बादल भी शामिल हैं। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा अब दिल्ली में मंत्री हैं।

अगर मैं भाजपा में जाने वाले कांग्रेसियों की सूची बनानी शुरू कर दूं तो इस पूरे आलेख की जगह छोटी पड़ जाएगी। इसलिए मैं उन तक सीमित रहूंगा जो भाजपा में मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री बने हैं या कांग्रेस में रहते हुए मुख्यमंत्री रहे हैं।

इस समय भाजपा के तीन मुख्यमंत्री कांग्रेस से आए हुए हैं- हिमंत विश्व शर्मा (असम), पेमा खांडू (अरुणाचल प्रदेश) और माणिक साहा (त्रिपुरा)। एन. बीरेन सिंह भी ऐसे ही एक नेता थे जिन्होंने हाल तक मणिपुर पर शासन किया।

ये चारों कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे। मोदी की मंत्रिपरिषद में आप ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजीजू, राव इंदरजीत सिंह, जितिन प्रसाद और रवनीत सिंह बिट्टू को गिन सकते हैं।

सिवाय एक के सभी प्रतिष्ठित कांग्रेसी परिवारों से आते हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों की सूची बनाएं जिन्होंने भाजपा का दामन थामा तो उनसे एक पूरी फुटबॉल टीम बन जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह, पेमा खांडू, अशोक चव्हाण, एसएम. कृष्णा, नारायण दत्त तिवारी, दिगंबर कामत, किरण कुमार रेड्डी, विजय बहुगुणा गिनते जाइए। पेमा खांडू को छोड़कर किसी को भाजपा से विशेष लाभ नहीं मिला सिवाय शायद संरक्षण के। या शायद उन्हें नुकसान से बचाव मिला।

कहा जाता है भाजपा एक चुंबक के समान है जहां सभी दलों के पराजित नेता जा पहुंचते हैं। इसके अलावा भाजपा साम, दाम, दंड और भेद का इस्तेमाल करके भी प्रतिद्वंद्वियों को तोड़ती है। वह जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है वे सभी भाजपा में जाकर पाक-साफ हो जाते हैं। भाजपा ने बड़े पैमाने पर दलबदल कराने के लिए फूट डालने के सिद्धांत में महारत हासिल कर ली है। दो-तिहाई को साथ ले आओ और कहो कि आप ही असली पार्टी हैं।

इससे दो प्रश्न उठते हैं। पहला, क्या प्रतिद्वंद्वी दलों को तोड़ने की यह प्रवृत्ति केवल अब शुरू हुई है? और दूसरा, जो हमने प्रारंभ में उठाया था कि आखिर क्यों अधिकांश दल टूट जाते हैं या अपनी प्रतिभाओं को खो देते हैं जबकि कुछ अन्य दल नहीं? कांग्रेस इस खेल की पुरानी उस्ताद रही है। वास्तव में, सुप्रीम कोर्ट के बोम्मई फैसले (11 मार्च, 1994) तक कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का उपयोग प्रतिद्वंद्वी सरकारों को बर्खास्त करने को आम चलन बना दिया था। फर्क यह है कि भाजपा अब अधिग्रहण के माध्यम से विस्तार पर पूरा ध्यान दे रही है। भाजपा यह बहुत बड़े पैमाने पर कर रही है।

दूसरा सवाल यह है कि आखिर क्यों अधिकांश दल टूट जाते हैं लेकिन कुछ नहीं? मैं केवल तीन का नाम लूंगा जो नहीं टूटते। भाजपा, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और वामपंथी दल। वामपंथियों में ट्रॉट्स्की, लेनिन, पेइचिंग और मॉस्को को लेकर कई बहसें और विभाजन हुए लेकिन वे एक मोर्चे में साथ बने रहे। विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता ही वह गोंद है जो दलों को साथ रखती है।

लोक सभा में कांग्रेस का सबसे कमजोर प्रदर्शन 2014 में 44 सीटों का था। 1984 के आम चुनाव में भाजपा दो सीटों पर सिमट गई थी, फिर भी वह एकजुट रही। वास्तव में, पार्टी की स्थापना (मूल रूप से भारतीय जनसंघ) के 75 वर्षों में 2014 तक उसने केवल छह वर्षों तक सत्ता संभाली थी। लेकिन कोई विभाजन नहीं हुआ, और सिर्फ एक महत्वपूर्ण दलबदल गुजरात में शंकरसिंह वाघेला का हुआ। इसके विपरीत कांग्रेस इतनी बार टूटी कि उनके पास वर्णमाला के अक्षर कम पड़ गए।

भाजपा से भी उल्लेखनीय अलगाव हुए हैं। पहला मामला बलराज मधोक का है जो जम्मू से स्वयंसेवक थे और जिन्होंने पार्टी अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनसंघ को 1967 के चुनावों में 35 सीटों के उच्चतम आंकड़े तक पहुंचाया। उनका अपने समकालीन अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी से टकराव हुआ क्योंकि वे अर्थव्यवस्था के मसले पर जनसंघ को तत्कालीन दक्षिणपंथी विचारधारा वाले अन्य संगठनों मसलन स्वतंत्र पार्टी आदि के साथ लाना चाहते थे। विरोधाभास यह था कि आरएसएस इस मामले में गांधीवाद के ज्यादा करीब था और मधोक इसे वामपंथी झुकाव के रूप में देखते थे या इंदिरा गांधी के विचारों से समानता मानते थे। 1973 में मधोक को जनसंघ के अंदर किनारे कर दिया गया और वे नाराज हो गए।

उन्होंने पार्टी के नेताओं, खासकर वाजपेयी पर तीखे हमले किए लेकिन किसी विरोधी दल में नहीं गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापकों में से एक मधोक एक दशक पहले 96 वर्ष की आयु में गुमनाम मौत मरे। 2010 में दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने उन्हें 1980 में मंत्री पद की पेशकश की थी लेकिन एक स्वयंसेवक होने के नाते वह इस लोभ में नहीं आए।

बाद में हमने कल्याण सिंह, उमा भारती और बीएस येदियुरप्पा जैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों की बगावत देखी लेकिन वे सभी लौट आए। ऐसे नेताओं में केवल एक ने ही थोड़ी कामयाबी हासिल की लेकिन वे टिके नहीं। वाघेला ने 1995 में भाजपा के 47 विधायकों के साथ बगावत की थी और केशुभाई पटेल और नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि इन लोगों ने उन्हें पार्टी में दरकिनार किया। वाघेला कांग्रेस के सहयोग से एक साल तक मुख्यमंत्री रहे। बाद में उन्होंने अपने गुट का कांग्रेस में विलय कर दिया। वह उसके टिकट पर दो बार सांसद चुने गए और 2004 में केंद्रीय कपड़ा मंत्री बने। इसके बाद धीर-धीरे वे कमजोर पड़ते गए। आज 85 साल की उम्र में वे अलग-थलग जीवन जी रहे हैं।

भाजपा और वाम दल लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहते हुए भी एकजुट रहे। मुलायम सिंह यादव द्वारा स्थापित समाजवादी पार्टी आश्चर्यजनक रूप से इस मामले में उनके समान ठहरती है। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद ओबीसी-मुस्लिम वोट बैंक वाली सभी पार्टियों में से यह सबसे ज्यादा टिकाऊ रही है। इसकी विचारधारा काफी स्पष्ट है और अखिलेश यादव ने अपने वोट बैंक का भरोसा बनाए रखा है।

जिस राजनीतिक शक्ति को इस पर मंथन करना चाहिए वह कांग्रेस है। इतने सारे क्षेत्रीय दल मसलन टीएमसी, राकांपा, वाईएसआरसीपी आदि इससे ही अलग हुए हैं। इसके अपने नेता लगातार अवसर खोजते रहे हैं। यह स्पष्ट है कि समय के साथ सत्ता ही इसकी मुख्य विचारधारा बन गई। जब सत्ता चली गई तो इसके कई नेता भी चले गए। अन्य क्षेत्रीय दलों की बात करें जिनमें टीएमसी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल हैं तो ये बस एक-परिवार वाली पार्टियां थीं। जब परिवार वोट जीतने में असफल रहा, तो ये टूट गईं।

अकाली दल का पतन भी इसी में निहित है कि धार्मिक विचारधारा में डूबा हुआ दल एक पारिवारिक उद्यम बन गया। अब तक भाजपा ने अपनी वैचारिक बुनियाद को बनाए रखा है। इसमें अक्सर असहमति होती है लेकिन विद्रोह नहीं। शाखा संस्कृति का दबाव, कैडर और आरएसएस के बीच गुरु-शिष्य संबंध इसे एकजुट रखता है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

वेश्या सुधार की कठिन समस्या को हल करने के लिये क्या कुछ करना चाहिये इसका भी स्पष्टीकरण हो जाता है।

महाशय जी यदि इसे शुरू रे आखीर तक लिख देते तो सारी कलई खुल जाती परन्तु चूहे के चेले दयानन्दियों की बीच बीच से प्रमाण कतर डालने की आदत कब छूटने लगी। यहाँ भी मीठा मीठा गप्प और कड़वा कड़वा थू को चरितार्थ किया गया है।

भगवान् ने इस प्रसङ्ग में जो आज्ञा की है उसका सार यह है कि कोई भी व्यसन एकदम छोड़ डालना महा कठिन है अतः बुद्धिमान् उसे शनैः शनैः छुड़ाया करते हैं। सो यदि अगणित पुरुषों से व्यभिचार करने वाली वेश्यायें दो बातों का नियम बांध लें तो उनका बहुत कुछ सुधार हो सकता है, पहिली बात (1) यदि कोई द्विज, वेश्या को दासी या ख्वाहिश के रूप में भोजन श्राच्छादन मात्र पर अपनी शरण में रखले तो उसी एक को अपना सर्वस्व समझ कर आत्मसमर्पण कर दें, तथा उसकी आज्ञाकारिणी बनकर सभ्य महिलाओं की भाति अपना शेष जीवन बिताये । इससे अनेक पुरुषों से व्यभिचार करने की पतित वृत्ति भी छूट जायेगी और योगक्षेम का प्रश्न भी हल हो जायगा।

दूसरी बात (2) प्रत्येक रविवार को उपवास करके किसी शान्त (विषय-वासनानिर्मुक्त एवं रागद्वेषरहित) वेद पुराणों के ज्ञाता विचक्षण ब्राह्मण से कथा वार्ता आदि सुने और उसका यथोचित सत्कार करे। ऐसा करने से %विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः इस गीता के सिद्धान्तानुसार यह उत्तरोत्तर विषयों से क्लान्त होकर समस्त देवताओं से भी पूजित हो जायगी, और अन्त में अखण्ड आनन्दमय मुक्तिपद को पायेगी। इस प्रकार यह प्रसंग समाप्त होता है।

क्रमशः ...

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस

ललित गर्ग

भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक, राष्ट्रीयता के समर्थक और सिद्धान्तवादी थे। जब कभी भारत की एकता, अखण्डता एवं राष्ट्रीयता की बात होगी तब-तब डॉ. मुखर्जी द्वारा राष्ट्रजीवन में किये गए योगदान की चर्चा अवश्य होगी। डॉ. मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झण्डा और अलग संविधान था। वहाँ का मुख्यमन्त्री (वजीरे-आजम) अर्थात् प्रधानमन्त्री कहलाता था। संसद में अपने भाषण में डॉ. मुखर्जी ने धारा-370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था कि

या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊँगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपना जीवन बलिदान कर दूँगा। उन्होंने तात्कालीन नेहरू सरकार को चुनौती दी तथा अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहे। अपने संकल्प को पूरा करने के लिये वे 1953 में बिना परमिट लिये जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। वहाँ पहुँचते ही उन्हें गिरफ्तार कर नजरबन्द कर लिया गया। 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गयी। डॉ. मुखर्जी निरन्तर राष्ट्र श्रद्धा के प्रतीकों का मान एवं रक्षण करते रहे। वे सदैव देशहित में स्वदेशी चेतना, स्वदेशी जीवन पद्धति, स्वदेशी वेशभूषा तथा स्वदेशी संस्कार के प्रकटीकरण पर बल दिया। वे सच्चे अर्थों में राष्ट्रधर्म का पालन करने वाले साहसी, निडर एवं जुझारु कर्मयोद्धा थे। जीवन में जब भी निर्माण की आवाज उठेगी, पौरुष की मशाल जगेगी, सत्य की आंख खुलेगी एवं अखण्ड राष्ट्रीयता की बात होगी, डॉ. मुखर्जी के अवदानों को सदा याद किया जायेगा।

डॉ. मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब से देश की बागडोर अपने हाथों में ली है, तब से कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने, भारतीय संस्कृति की शिक्षा एवं संस्कार को आधार मानते हुए सारे विश्व में इसके प्रसार के लिए वे अग्रदूत की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मोदी न केवल भारतीय संस्कृति के ज्ञान को माध्यम बनाकर विश्व समुदाय को जीवन जीने का नवीन मार्ग बता रहे हैं, बल्कि भारत को एक बार फिर जगतगुरु के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉ. मुखर्जी के दृष्टिकोण एवं संकल्पों को श्री मोदी ने 'माय आइडिया ऑफ इंडिया' के रूप में कई बार संसार के समक्ष भी रखा है। मोदी ने डॉ. मुखर्जी के व्यापक दृष्टिकोण एवं भारत को लेकर उनके सपनों को निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से प्रस्तुति दी है। देश और दुनिया में उनकी विचारधारा एवं सपनों को प्रभावी ढंग से न केवल प्रस्तुति दी है बल्कि उन अधूरों सपनों को पूरा भी करने की ओर डग भरे हैं।

डॉ. मुखर्जी का जीवन बहुत संघर्षभरा रहा, अपनी राष्ट्रवादी नीतियों के कारण उन्हें बहुत से विरोध एवं उपेक्षाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने संकल्प पर अडिग रहे। उनके अनुसार भारत कर्मभूमि, धर्मभूमि एवं पुण्यभूमि है, यहां का जीवन विश्व के लिये आदर्श है।

युद्ध के खिलाफ एकजुट दिखे जी-7 के देश

अनिल त्रिगुणायत

फ्रांस के एवियन शहर में संपन्न हुई जी-7 की बैठक बेहद सफल रही। पहला कारण तो यही है कि जिस ईरान-अमेरिका शांति समझौते पर होने वाले दस्तखत का इंतजार हो रहा था, उस पर जी-7 की बैठक में ही दस्तखत हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने समझौते पर हस्ताक्षर कर पश्चिम एशिया में फरवरी के अंत से चल रहे युद्ध के औपचारिक खात्मे की घोषणा की।

कुल 14 बिंदुओं वाले इस समझौते को एमओयू, यानी सहमति पत्र बताया गया है। इसके मुताबिक, ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनायेगा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को खोला जायेगा। समझौते में कहा गया है कि अब से कोई भी पक्ष सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करेगा, दोनों देश एक-दूसरे को धमकी भी नहीं दे सकेंगे तथा लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान किया जायेगा। हालांकि, ईरान का कहना है कि इस्राइल अगर लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रखता है, तो वह समझौते का उल्लंघन होगा और वैसी स्थिति में जरूरी कदम उठाये जायेंगे।

जी-7 ने अमेरिका-ईरान शांति समझौते का स्वागत किया है। चूंकि ईरान-अमेरिका युद्ध और उससे भी चार साल पहले शुरू हुए यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका-यूरोप के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गये थे, ऐसे में, ट्रंप और पेजेश्कियान के बीच हुए दस्तखत ने यूरोप-अमेरिका के बीच की खटास भी अब काफी हद तक दूर कर दी है। यह घटनाक्रम वैश्विक समन्वय के लिए सुखद है।

जी-7 बैठक की दूसरी उल्लेखनीय बात यह रही कि यूरोपीय देशों ने पिछले चार साल से भी अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस पर दबाव तेज करने पर सहमति व्यक्त की और अमेरिका को भी इस सिलसिले में अपनी ओर से पहल करने के लिए कहा। गौर करने की बात है कि जी-7 की बैठक में ही ब्रिटेन और कनाडा ने रूस के

खिलाफ नये प्रतिबंधों की घोषणा भी की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जी-7 की बैठक में उपस्थित थे और ट्रंप से उनकी बातचीत भी हुई। ट्रंप ने कहा कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता करना चाहिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति का यह भी कहना था कि उन्होंने आठ युद्ध खत्म किये हैं और यूक्रेन युद्ध को वह खत्म होते हुए देखना चाहते हैं। यदि यूक्रेन युद्ध जल्दी खत्म होता है, तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात और बातचीत को मैं जी-7 की तीसरी बड़ी उपलब्धि मानता हूं। भारत जी-7 का सदस्य नहीं है, वह इस संगठन में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर बुलाया जाता है। पर एक तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप और मैक्रों के बीच दिखाई पड़े।

यह तस्वीर ही अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की धमक और उसका महत्व बताने के लिए काफी है। वैश्विक परिदृश्य में भारत का महत्व सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। अब देखिए, ब्रिटेन के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने से लागू होने वाला है, यूरोपीय संघ के साथ एफटीए पर इस साल के अंत तक दस्तखत होने वाला है, जर्मनी से हमें सबमरिन, तो फ्रांस से राफेल की अगली खेप मिलने वाली है। बल्कि आने वाले दिनों में राफेल मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाये जाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें भारत के महत्व के बारे में बताती हैं।

जी-7 की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बहुप्रतीक्षित मुलाकात हुई। हालांकि, इससे पहले जी-7 के आउटरीच सेशन में भी दोनों की मुलाकात हुई। द्विपक्षीय बैठक में ट्रंप और मोदी ने लगभग पांच मिनट तक बैठकर विभिन्न मुद्दों पर बात की। इन दोनों की पिछली मुलाकात फरवरी, 2025 में व्हाइट हाउस में हुई थी। मोदी और ट्रंप की मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब दोनों देशों के बीच कई विवाद चल रहे थे, जिनमें हाल ही में अमेरिकी हमले में भारतीय नाविकों की मौत का मामला भी था।

ऐसे में, जी-7 की बैठक में ट्रंप-मोदी की मुलाकात 'ब्रेकिंग द आइस' रही। यानी दोनों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघली है। मुझे लगता है कि यह एक अहम और रिश्तों की फिर से शुरुआत वाली बैठक थी। दोनों नेता सोलह महीने से नहीं मिले थे। इस बार बेशक पहले जैसा गले मिलना नहीं दिखा, लेकिन ट्रंप फिर भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने की कोशिश कर रहे थे। जो हमने देखा, उसके अनुसार यह जरूरी था कि मुश्किल मुद्दों पर बात हो। जैसे कि हमारे नाविकों की हत्या और उनकी सुरक्षा। अब भी व्यापार समझौते जैसे कई मुद्दे बाकी हैं, लेकिन यह बैठक दोतरफा रिश्तों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से कहा कि पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों की दिशा में जो प्रगति हुई है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जबकि ट्रंप ने एक बात यह कही कि अगर भारत पर हमला होता है, तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा, भले ही कोई लिखित समझौता न हो। मेरी समझ में इसका अर्थ यह है कि ट्रंप के राष्ट्रपति काल में अगर भारत पर कोई हमला होता है, तो भारत की मदद के लिए अमेरिका तत्काल आगे आयेगा। ट्रंप ने जल्दी ही भारत का दौरा करने की भी बात कही है।

उन्होंने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई और हम ट्रेड डील कर रहे हैं। ट्रंप ने इस बैठक में जी-2 का भी जिक्र किया, जो अमेरिका और चीन के विजन की बात करता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत पश्चिम एशिया में कोई भूमिका निभाता है, तो उनका जवाब था कि भारत हर चीज में बड़ी भूमिका निभाता है और जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, भारत बड़ी भूमिका निभाता रहेगा। ट्रंप की यह टिप्पणी वैश्विक परिदृश्य में प्रधानमंत्री मोदी का महत्व बताती है।

बेशक, भारत के लिए भी जी-7 की बैठक बेहद लाभकारी साबित हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा यूरोपीय संघ के नेताओं, जर्मनी के चांसलर, यूएइ के राष्ट्रपति तथा ब्रिटेन व कनाडा के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की। मेजबान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष तथा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष से भी मुलाकात की तथा भारत-यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि भारत और इयू के बीच बढ़ता सहयोग आज के वैश्विक माहौल में शांति, स्थिरता और समृद्धि को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। कुल मिलाकर, जी-7 की बैठक भारत समेत पूरे विश्व के लिए उपलब्धियों से भरी रही।

आज का इतिहास

1887 कनाडा की संसद ने रॉकी पर्वत पार्क अधिनियम पारित किया, जिससे देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनफ नेशनल पार्क बना।
1894 बैरन पियरे डी कुबर्टिन की पहल पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पेरिस के सोरबोन में स्थापना।
1919 स्वतंत्रता के एस्टोनियाई युद्ध-एस्टोनियाई सैनिकों ने चार दिन बाद क्षेत्र को फिर से तैयार करने के लिए लाटविया के सीसस के पास प्रो-जर्मन सरकार की स्थापना की।
1926 कॉलेज बोर्ड ने पहले SAT का संचालन किया, जो यूनाइटेडस्टेट्स में विश्वविद्यालय और कॉलेज के प्रवेश के लिए एक प्रमुख परीक्षण था।
1946 कनाडा का सबसे बड़ा तटवर्ती भूकंप, 7.3 मेगावॉट, मापने के लिए मारा गया, लेकिन वैंकूवर द्वीप, लेकिन केवल दो हताहतों का कारण बना, क्योंकि इसके उपरिकेंद्र के पास कई आबादी वाले क्षेत्र थे।
1956 जमाल अब्दुल नासिर मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए।
1956 गमाल अब्देल नासर मिस्र के राष्ट्रपति बने, एक ऐसा पद जो उन्होंने 1970 में अपनी मृत्यु तक कायम रखा।
1960 जापान और अमेरिका के बीच सुरक्षा समौझाता हुआ।
1972 1964 के यूनाइटेड स्टेट्स सिविल राइट्स एक्ट के शीर्षक IX को किसी भी शैक्षिक प्रोग्रामरिंग फेडरल फंड्स में लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसने महिलाओं के खेल के छात्र एथलीटों में भारी वृद्धि की अनुमति दी थी।
1982 चीनी अमेरिकी विन्सेन्ट चिन की मौत अमेरिका के मिशिगन के हाईलैंड पार्क में अकोमा में पिटाई के बाद हो गई, दो ऑटोमोटिव वर्करों ने, जिन्होंने उसे जापानी के लिए हतोत्साहित किया था और जो जेजेओ ऑटो कंपनियों की सफलता को लेकर नाराज थे।
1983 पोप जॉन पॉल द्वितीय ने पोलैंड के स्वतंत्र मजदूर संघ आंदोलन सॉलिडैरिटी के संस्थापक और नेता लेच वालेसा से निजी मुलाकात की थी। 1981 में पोलैंड में सामाजिक तनाव को देखते हुए मार्शल लॉ घोषित किया था और सॉलिडैरिटी पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था।
1991 वीडियो गेम सोनिक द हेजहोग को पहली बार रिलीज़ किया गया था, जिसमें सेगा उत्पत्ति 16-बिट कंसोल को बड़े पैमाने पर लोकप्रियता में बदल दिया गया था।
1991 अफ्रीकी देश माल्दोवा ने आजादी की घोषणा की।
1996 शेख हसीना वाजेद ने बंगलादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।

क्या आरएसएस की भारत की जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए?

राम पुनियानी

आरएसएस द्वारा प्रशिक्षित प्रचारक नाथूराम गोडसे ने सिर्फ इस वजह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छाती को तीन गोलियों से छलनी कर दिया था कि गांधी मानते थे कि देश सभी धर्मों के लोगों का है, जबकि गोडसे और उसके पितृ संगठनों आरएसएस-हिन्दू महासभा का मानना था कि देश केवल हिन्दुओं का है। गांधीजी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ नफरत फैलाई गई, जिसके नतीजे में बिल्कुल नजदीक से गोलियां चलाकर गांधीजी की हत्या कर दी गई। इस गुनाह के कारण भारत के तत्कालीन उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री सरदार पटेल ने 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया और उसके बाद लिखा कि उनके सभी भाषण नफरत भरे होते थे। इस जहर का अंतिम परिणाम यह हुआ कि देश को गांधीजी के बहुमूल्य जीवन की कुर्बानी देनी पड़ी।'' यह प्रतिबंध संघ द्वारा यह वायदा करने के बाद हटाया गया कि उसका एक लिखित संविधान होगा और वह सिर्फ एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में कार्य करेगा।

हकीकत यह है कि आरएसएस सांस्कृतिक संगठन की भेष में एक राजनैतिक संगठन है। उसने पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीव्हीपी) की स्थापना की और बाद में भाजपा के पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका नया अवतार भाजपा वर्तमान में केन्द्र और कई राज्यों की सरकार चला रही है। संघ का दावा है कि उसका खर्चा दशहरे के दिन मिलने वाली गुरू दक्षिणा की रकम से चलता है। आयकर अधिकरण ने पता नहीं क्यों आय के इस स्त्रोत को कर मुक्त घोषित कर दिया। वह अपने कार्यक्रमों और शाखाओं के संचालन पर (जो शासकीय भूमि पर भी किया जाता है) अंधाधुध पैसा खर्च कर रही है। उसके पथ संचलनों में कितनी राशी व्यय होती है, इसे गोपनीय रखा जाता है। कहा जाता है कि आरएसएस के दिल्ली कार्यालय के निर्माण पर 100 करोड़ से अधिक का व्यय हुआ है। ये सारे भारी-भरकम खर्चे सरकारी जांच-पड़ताल की पहुंच से कोसों दूर हैं।

सांस्कृतिक संगठन होने के इस दावे को सरकार और ज्यादातर लोगों द्वारा मान लिया गया और अब तक संघ तेजी से विस्तार करते हुए लाखों शाखाओं की स्थापना कर चुका है और कई लाख स्वयंसेवक उससे जुड़ चुके हैं। नेहरू को संघ की प्रकृति का अहसास बहुत जल्दी हो गया था। लेकिन कुछ साल पहले तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित किसी भी राजनैतिक दल ने इन मुद्दों से जुड़े सवाल नहीं उठाए जिसके चलते यह संगठन कानूनी प्रावधानों और नैतिक मूल्यों को ताक पर रखते हुए मनमानी कर रहा है। कांग्रेस ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी यह गलती सुधारी है और विशेषकर राहुल गांधी आरएसएस के संबंध में तर्कपूर्ण और विधिसम्मत सवाल उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा था कि आरएसएस से जुड़े लोग गांधीजी की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, जिसे लेकर उन पर मुकदमा चला। आरएसएस से दो-दो हाथ करने की इसी नीति के अंतर्गत अब कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने आरएसएस से कहा है कि वह अपना पंजीयन करवाए और भारतीय राज्य के प्रति जवाबदेह बने।

उन्होंने दिनांक 13 जून को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखे एक पत्र में उनसे संगठन की वैधानिक स्थिति, वित्तीय व्यवस्था, पदाधिकारियो व कर संबंधी नियमों के अनुपालन एवं उसकी गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगीं। आरएसएस आधिकारिक रूप से यह दावा करता है कि देश एवं देश के बाहर उसकी 60 हजार शाखाएं हैं और करोड़ों स्वयंसेवक हैं। खड़गे ने सार्वजनिक रूप से जारी अपने वक्तव्य में कहा कि यह मात्र एक वैधानिक आवश्यकता नहीं है बल्कि इसका नैतिक पक्ष भी है। उन्होंने लिखा, उसकी गतिविधियां जिस बड़े पैमाने पर संचालित होती हैं, और उसके व्यापक प्रभाव एवं पहुंच के मद्देनजर आरएसएस से उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, जवाबदेही एवं संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करवाया ही जाना चाहिए।''

इस पत्र को सार्वजनिक तौर पर जारी किया गया है। अपनी प्रतिक्रिया में आरएसएस के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत ने कहा कि वे इस पत्र को नजरअंदाज कर रहे हैं और इसका जवाब नहीं देंगें। इस प्रतिक्रिया से ऐसा महसूस होता है कि भागवत मानते हैं कि वे और उनका संगठन कानून और भारतीय संविधान के ऊपर हैं। वैसे भी आरएसएस भारतीय संविधान में आस्था नहीं रखता। भारतीय संविधान के लागू होने के तीन दिन बाद आरएसएस के मुखपत्र आर्गनाईजर ने अपने संपादकीय में कहा था कि यह संविधान, जिसका मसौदा डॉ अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया है एवं भारतीय संविधान सभा द्वारा अनुमोदित किया गया है, हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पवित्र ग्रंथों के यशस्वी मूल्यों को शामिल नहीं किया गया है। आरएसएस के एक पूर्व प्रमुख राजेन्द्र सिंह ने कहा था कि संविधान को खारिज कर दिया जाना चाहिए। एक अन्य प्रमुख के। सुदर्शन ने तो यह तक कहा कि संविधान पश्चिमी मूल्यों पर आधारित है अत: इसे ऐसे संविधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जो पवित्र भारतीय ग्रंथों पर आधारित हो। सन् 2024 में लगाए गए 400 पार के नारे का एक उद्देश्य लोकसभा में संविधान बदलने के लिए जरूरी संख्या हासिल करना भी था।

भागवत द्वारा अपने संगठन को संविधान के ऊपर मानने का कारण यह तथ्य भी हो सकता है कि हालांकि उनके पास भारत सरकार का कोई आधिकारिक पद नहीं है, फिर भी उन्हें प्रधानमंत्री के स्तर की सुरक्षा हासिल है। प्रियंक खड़गे द्वारा कही गई बातों की प्रतिक्रिया में भागवत ने कहा ''हम गोपनीयता नहीं बरतते। हमारा कामकाज खुले मैदानों में चलता है। हम लोगों को आमंत्रित कर उन्हें अपने बारे में बता रहे हैं। ये सारे आक्षेप सिर्फ सियासती है और तरह-तरह के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं... हिन्दू धर्म पंजीकृत नहीं है, और बहुत सी अन्य संस्थाएं भी पंजीकृत नहीं हैं''। सवाल यह है कि क्या इन लोगों ने बाबरी मस्जिद को ढ़हाए जाने की योजना पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की थी?

यहाँ यह स्मरणीय है कि अमेरिका के कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ) ने हाल में यह अनुशंसा की थी कि अमरीकी सरकार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर लक्षित प्रतिबंध लगाने चाहिए। प्रस्तावित कदमों में संगठन की संपत्तियों को फ्रीज करना और उसके सदस्यों को वीजा न देना शामिल हैं।

भागवत द्वारा संघ का पंजीयन न कराने के पक्ष में एक तर्क यह दिया कि हिन्दू धर्म भी तो पंजीकृत नहीं है! हिन्दू धर्म और आरएसएस को बराबरी का दर्जा देने वाला यह वक्तव्य एक तरह से हिन्दू धर्म का अपमान है। हिन्दू धर्म के कई सम्प्रदाय हैं जैसे नाथ, तंत्र, शैव, सिद्धांत और भक्ति। आरएसएस जिस हिन्दुत्व का प्रचार करता है वह ब्राम्हणवाद है जो जातिगत एवं लैंगिक ऊंच-नीच पर आधारित है। कम से कम यह तो कहा ही जा सकता है कि यह तर्क किसी भी तरह से कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

यह आश्चर्यजनक नहीं है कि आरएसएस के पंजीयन की मांग उठाई जा रही है। आश्चर्य इस बात का है कि यह मांग पहले क्यों नहीं उठी। आरएसएस के विचारों के प्रति सहानुभूति रखने वाले कई सरकारी अधिकारी उसके हितों की रक्षा करने में जुटे हुए हैं। दान एवं खर्चों से संबंधित नियम ही पंजीयन की अनिवार्यता की सबसे बड़ी वजह होने चाहिए। इसी तरह सांस्कृतिक संगठन होने का दावा करते हुए आरएसएस द्वारा राजनैतिक गतिविधियां करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही प्रतिबंध हटाने का अनुरोध करते समय किए गए वायदों पर अमल न किए जाने के मसले को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। वक्त आ गया है कि भारतीय संविधान और भारतीय राष्ट्रवाद को महत्व दिया जाए और न सिर्फ आरएसएस वरना ऐसे सभी अन्य ऐसे संगठनों से पंजीयन करवाने को कहा जाए, जिनके लिए ऐसा करना अपेक्षित हो।

अमेरिका-ईरान समझौते से जगी उम्मीदें

देवेश त्रिपाठी

इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि एक तरफ दुनिया जहां अमेरिका और ईरान से स्थायी शांति की ओर बढ़ने की उम्मीद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस्राइल द्वारा लेबनान में जारी हमलों के बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है और ट्रंप बार-बार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, जिससे एक बार फिर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम शांति समझौते से पश्चिम एशिया में तनाव खत्म होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन महज चौबीस घंटों में ही यह दरकती नजर आई। समझौते में ईरान ने एक शर्त रखी है कि इस्राइल उन इलाकों से पीछे हटने का वादा करे, जिन पर उसने युद्ध के दौरान दक्षिणी लेबनान में कब्जा किया था। लेबनान में इस्राइली सैन्य गतिविधियों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी अमेरिका की है, जबकि समझौते को लेकर इस्राइल में गहरी नाराजगी है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा इस्राइल की कड़ी आलोचना और नसीहत ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों में दरार और अलग-अलग रणनीतिक प्राथमिकताओं को उजागर किया है। एक तरफ जहां ईरानी सेना ने दक्षिणी लेबनान पर इस्राइली हमलों के जवाब में फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का दावा किया है, वहीं दूसरी तरफ वार्ता सफल नहीं होने की स्थिति में ट्रंप द्वारा अमेरिकी टोल टैक्स की चेतावनी ने तेल आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नई आशंकाएं पैदा कर दी हैं। इससे एक अलग तरह की होड़ शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं, जिसके लिए काफी हद तक अमेरिका ही जिम्मेदार है। ईरान और इस्राइल में दशकों से तनातनी और संघर्ष जारी रहा

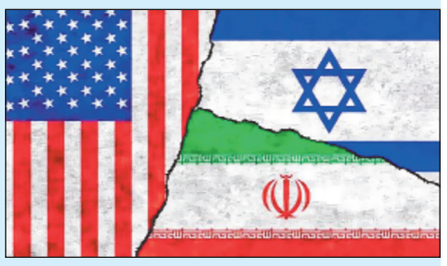

है, जिसमें अमेरिका इस बहाने से कूद पड़ा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से पश्चिम एशिया में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। पर विडंबना यह है कि जिस युद्ध को शुरू करके अमेरिका हथियारों की होड़ को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, उसी युद्ध ने ईरान को होर्मुज पर नियंत्रण जैसी रणनीतिक ताकत दे दी, जिसके बल पर वह अमेरिका से सौदेबाजी कर रहा है। अगर इसी तरह दुनिया के अन्य देश भी महत्वपूर्ण मार्गों पर टोल वसूलने लगे, तो इससे एक अलग तरह की होड़ शुरू हो जाएगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बेशक कह रहे हैं कि वार्ता में काफी प्रगति हुई है और अमेरिका व ईरान मिलकर पश्चिम एशिया में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ट्रंप ने ईरान को जो चेतावनी दी है, कि वह वहां अपने प्रॉक्सी समूहों को अशांति फैलाने से तुरंत रोके, अन्यथा अमेरिका उस पर फिर से जोरदार हमला करेगा, कुछ और ही संकेत दे रही है। जाहिर है, इस तरह की बयानबाजियों से अनिश्चितता तो बढ़ेगी ही, स्थायी शांति की उम्मीद भी धूमिल नजर आ रही है। इस जटिल त्रिकोणीय संघर्ष में किसी भी पक्ष के लिए बड़बोलेपन से ज्यादा कूटनीतिक लचीलापन ही एकमात्र स्थायी समाधान हो सकता है।

उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर और नई आर्थिक शक्ति बनने का सफर

कांतिलाल मांडोत

उत्तर प्रदेश लंबे समय तक देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य के रूप में जाना जाता रहा, लेकिन अब उसकी पहचान तेजी से बदल रही है। आज उत्तर प्रदेश केवल आबादी के आधार पर नहीं, बल्कि विकास, निवेश, उद्योग, आधारभूत संरचना और आर्थिक प्रगति के कारण देश की अग्रणी शक्ति के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में जिस गति से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है, उसने प्रदेश की छवि को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान प्रदान की है। कभी कानून-व्यवस्था और पिछड़ेपन की चर्चा के लिए सुर्खियों में रहने वाला उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक कॉरिडोर और निवेश परियोजनाओं के लिए जाना जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान प्रदेश के विकास मॉडल को रेखांकित करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि धरातल पर उतरती हैं और जनता तक उनका लाभ पहुंचता है। उन्होंने कहा कि उन्नाव को स्टेट कैपिटल रीजन का हिस्सा बनाया गया है और लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यह परियोजना न केवल परिवहन को गति देगी, बल्कि औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगी।

प्रदेश में विकसित हो रहे एक्सप्रेसवे नेटवर्क को उत्तर प्रदेश की प्रगति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य कर रही हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नाव के लोग अब लखनऊ को बाईपास करते हुए सीधे दिल्ली और प्रयागराज तक पहुंच

सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए डिफेंस कॉरिडोर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्नाव में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए लगभग 700 एकड़ भूमि तथा औद्योगिक क्लस्टर के लिए 200 एकड़ भूमि तैयार की गई है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि उद्योगों के विस्तार से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय बदलाव देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यह कहते रहे हैं कि निवेश और विकास के लिए सुरक्षित वातावरण आवश्यक है। यही कारण है कि प्रदेश में अपराध और माफिया गतिविधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि देश और विदेश के निवेशकों का विश्वास प्रदेश में बढ़ा है। निवेशकों की बढ़ती रुचि के कारण उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो भविष्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का आधार बनेंगे।

प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास और किसानों के उत्थान को भी समान महत्व दे रही है। कानपुर में आयोजित प्राकृतिक कृषि प्रोत्साहन कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक खेती को समय की आवश्यकता बताया। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। सरकार का मानना है कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन लागत कम होगी, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को जीवामृत, बीजामृत तथा गो-आधारित प्राकृतिक खेती की जानकारी देकर उन्हें आधुनिक और टिकाऊ कृषि पद्धतियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

किसानों के साथ-साथ गरीब और वंचित वर्गों के लिए भी अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन वितरण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं ने लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और सिफारिश के सीधे पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। इससे शासन के प्रति जनता का विश्वास मजबूत हुआ है।

आधारभूत संरचना के विकास में भी उत्तर प्रदेश ने नई उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश में नए एयरपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं और कई हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है। अयोध्या, कुशीनगर और जेवर जैसे एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। सड़क, रेल और हवाई परिवहन के क्षेत्र में हो रहे निवेश से प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता अब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सड़कों की बराबरी कर रही है।

धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम, मथुरा-वृंदावन और प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों के विकास ने पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इससे स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

अपने दल से अलग क्यों जा रहे सांसद

सुरेश हिंदुस्तानी

राजनीति में अवसर की तलाश करना आज के राजनेताओं का प्रिय विषय बनता जा रहा है। सीधे शब्दों इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि राजनीति अब सेवा का मार्ग न होकर अवसरवादिता के आवरण को ओढ़ चुकी है। विपक्षी दलों खास कर तृणमूल कांग्रेस और अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसदों का अलग होना कहीं न कहीं यही संकेत करता है कि ये सांसद अपने पार्टी के सिद्धांतों से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं रखते थे, लिहाजा उन्होंने अपना खुद का एक राजनीतिक पाला बना लिया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि अब विपक्ष की संभावनाएं धूमिल होती दिखाई दे रही हैं। विपक्ष की राजनीति का एक ही मुद्दा रह गया है, वह है आरोप की राजनीति। तुम आरोप लगाते रहो, हम काम करते जाएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कुछ इसी प्रकार का खेल चल रहा है। यह बात सच है कि केवल आरोप लगाने की राजनीति के माध्यम से सत्ता का सिंहासन प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय हित और जनहित की ओर जाना ही होगा। आज की राजनीतिक स्थिति का विचार किया जाए तो यह कहना उचित ही होगा कि भाजपा का प्रचार सत्ता पक्ष की ओर से कम विपक्ष की ओर से ज्यादा किया जा रहा है। आज विपक्ष के नेताओं के बयान बिना भाजपा के अधूरे ही रहते हैं।

राजनीति में कब क्या हो जाए, कोई भी व्यक्त नहीं कर सकता। इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि आज का राजनेता किसी न किसी हेतु के लिए ही राजनीति कर रहा है, ऐसे राजनेता की न तो किसी दल से वैचारिक समानता होती है और न ही किसी राजनीतिक नेतृत्व के प्रति निष्ठा ही रहती है। ऐसे राजनेता अपने स्वार्थ को पूरा करने के अवसर की तलाश करते हैं। वर्तमान में विपक्षी राजनीतिक दलों के जो सांसद अपने दलों को छोड़ रहे हैं या छोड़ने का मन बना रहे हैं, वे अब शायद यह समझने लगे हैं कि उनका भविष्य अपने दल के साथ सुरक्षित नहीं है। इसका कारण यही है कि भारत की जनता को भारत के विकास की राजनीति पसंद आने लगी है। दूसरा बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि भाजपा की ताकत लगातार बढ़ती

जा रही है। विपक्ष के राजनीतिक दल पूरा जोर लगाने के बाद भी पराजित होते जा रहे हैं। भविष्य में इनको सफलता मिलेगी, इसकी फिलहाल कोई गुंजाईश भी नहीं है।

वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक और सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़कर अलग राह पर जा चुके हैं। इससे ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत भी बेअसर हो गई है। और इसी कारण उनकी पार्टी आज एक डूबता हुआ जहाज की परिकल्पना को चरितार्थ करती हुई दिखाई दे रही है। कहा जाता कि जब किसी के ताकत होती है, तो उसके पास अनेक लोग खड़े हो जाते हैं, और उसके शक्तिहीन होने पर कभी खास बनने वाले लोग भी दूरी बना लेते हैं। विपक्ष की राजनीति के लिए सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात यह है कि विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए एक समय ताल ठोकने वाली ममता बनर्जी के पास अब पहले जैसा रुतबा नहीं होगा और न ही विपक्ष में उनकी बात को कोई तबज्जो मिलेगा। इतना ही नहीं एक समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुखर होने वाली ममता के लिए अब कांग्रेस के नेतृत्व में राजनीति करने की मज़बूरी बन गई है, जो ममता बनर्जी को न तो पहले स्वीकार था और न ही वे अब स्वीकार करेंगी।

जहाँ तक तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों के अपने दल से बागी होने की बात है तो यह कहना समीचीन ही होगा कि आज के राजनीतिक परिदृश्य में विपक्ष के भविष्य की संभावनाओं पर एक बहुत बड़ा विराम सा लगा हुआ दिखाई देता है। विपक्ष के राजनीतिक दल किसके नेतृत्व में एक होंगे, यह बड़ा सवाल है। जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों के वे नेता जो हाँ में हाँ मिलाते हुए राजनीति करते थे वे अब प्रासंगिक होने लगे हैं। इनका प्रासंगिक होना ही विपक्षी एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि शक्ति केंद्र एक स्थान पर होता है तो उसकी बात का महत्त्व होता है, लेकिन यही शक्ति जब विभाजित हो जाती है, तब वह शक्तिहीन की श्रेणी में ही आती है। आज विपक्ष के राजनीतिक दल किसी एक दल के नेतृत्व में आने के लिए तैयार नहीं हैं। जहाँ तक क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व की बात है तो वह कम से कम अपने प्रभाव क्षेत्र वाले राज्य में किसी दूसरे दल को अपने ऊपर प्रभावी होने नहीं देगा।

वर्तमान राजनीति का अध्ययन किया जाए तो विपक्ष की राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ही बोलबाला है। विपक्ष की ओर ये दोनों दल ही प्रभावी अस्तित्व में हैं। लेकिन कांग्रेस की नियति ऐसी हो गई है कि वह बिना किसी सहारे के आगे नहीं बढ़ सकती। उसको हमेशा क्षेत्रीय दलों की बैसाखी चाहिए। मुख्य बात यह है कि क्षेत्रीय दलों के पास स्वयं की ताकत ख़त्म होती जा रही है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की बात है तो वह पारिवारिक पृष्ठभूमि से बने राजनेता होने के कारण केवल उत्तरप्रदेश की राजनीति तक ही सीमित हैं। यह बात सही है कि उत्तरप्रदेश में बिना समाजवादी पार्टी के कोई गठबंधन हो ही नहीं सकता। अगर होगा भी तो उसकी प्रासंगिकता नहीं के बराबर ही होगी।

विपक्ष के सपने को तार तार करने के लिए कौन जिम्मेदार है? उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद यह कहते हुए अलग हुए हैं कि ठाकरे की पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है। यह बात शत प्रतिशत सही भी है। इसलिए जो नेता विचार की राजनीति के सहारे चल रहा था, उसको तालमेल बनाने में असहज ही होगा। इसके अलावा विपक्ष की पूरी राजनीति तुष्टिकरण को ज्यादा महत्त्व देने की रही है। यह विचार राष्ट्रीय राजनीति के लिए अत्यंत घातक है। आज देश को सकारात्मक राजनीति की आवश्यकता है। देश की जनता भी ऐसा ही चाहती है। इसलिए विपक्षी दलों को जन भावनाओं के अनुसार ही चिंतन और मंथन करना होगा। अगर ऐसा करते हैं तो उनको भविष्य के सपने बुनने का भी अधिकार है। और इस पर ध्यान नहीं दिया तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब पूरी पार्टी में केवल कुछ ही नेता बचेंगे।

सत्ता पक्ष में जाने के बाद क्या बागी सांसदों को टिकट मिलेगा?

सौरभ वार्ष्णेय

भारतीय राजनीति में दल-बदल कोई नई घटना नहीं है। समय-समय पर विभिन्न दलों के नेता और सांसद राजनीतिक परिस्थितियों, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं या वैचारिक मतभेदों के कारण अपने दल छोड़कर दूसरे दलों का दामन थामते रहे हैं। हाल के वर्षों में कई राज्यों में यह प्रवृत्ति और अधिक बढ़ी है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि सत्ता पक्ष में शामिल होने वाले बागी सांसदों को क्या अगले चुनाव में टिकट मिलेगा? राजनीति में टिकट का निर्धारण केवल निष्ठा के आधार पर नहीं होता, बल्कि जीत की संभावना, जनाधार और पार्टी की रणनीति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सत्ता पक्ष आमतौर पर उन नेताओं को अपने साथ जोडना चाहता है जो चुनावी दृष्टि से लाभकारी साबित हो सकते हैं। इसलिए यदि कोई बागी सांसद अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार रखता है और उसके आने से पार्टी को राजनीतिक फायदा होता है, तो उसे टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि यह भी सच है कि किसी दल में वर्षों से कार्य कर रहे पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए ऐसे फैसले असंतोष का कारण बन सकते हैं। जब बाहर से आए नेता को प्राथमिकता मिलती है, तो संगठन के भीतर नाराजगी बढने का खतरा रहता है। कई बार यही नाराजगी चुनावी नुकसान का कारण भी बन जाती है। इसलिए राजनीतिक दलों को संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। दूसरी ओर, बागी सांसदों के सामने भी चुनौती कम नहीं होती। दल बदलने के बाद उन्हें नए दल की विचारधारा, संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता साबित करनी पड़ती है। केवल सत्ता पक्ष में शामिल हो जाना टिकट या राजनीतिक भविष्य की गारंटी नहीं है। यदि पार्टी नेतृत्व को लगता है कि संबंधित नेता चुनाव जिताने में सक्षम नहीं है, तो टिकट किसी अन्य उम्मीदवार को भी दिया जा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दल-बदल की बढ़ती घटनाएं राजनीतिक सिद्धांतों और जनादेश की भावना पर भी सवाल खड़े करती हैं। मतदाता किसी उम्मीदवार के साथ-साथ उसकी पार्टी और विचारधारा को भी ध्यान में रखकर मतदान करता है। ऐसे में बार-बार होने वाले राजनीतिक पलायन से जनता के बीच विश्वास का संकट पैदा होना स्वाभाविक है। बागी सांसदों को टिकट मिलेगा या नहीं, इसका निर्णय राजनीतिक समीकरणों, जनाधार, संगठनात्मक संतुलन और चुनावी संभावनाओं पर निर्भर करेगा। लेकिन यह अपेक्षा अवश्य की जानी चाहिए कि राजनीति में अवसरवादिता के बजाय जनसेवा, सिद्धांत और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता मिले। यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनावों से नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की निष्ठा, सिद्धांतों तथा जनसेवा की भावना से तय होती है। दुर्भाग्यवश, हाल के वर्षों में दल-बदल, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और सत्ता प्राप्ति की राजनीति ने अवसरवादिता को बढ़ावा दिया है। इससे जनता के बीच राजनीति की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगने लगे हैं। राजनीति का मूल उद्देश्य समाज और राष्ट्र की सेवा है। जनता अपने प्रतिनिधियों को इस विश्वास के साथ चुनती है कि वे उनके हितों, समस्याओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन जब निर्वाचित प्रतिनिधि व्यक्तिगत लाभ, पद या सत्ता के लिए बार-बार राजनीतिक निष्ठा बदलते हैं, तो मतदाताओं का विश्वास कमजोर होता है। लोकतंत्र में यह स्थिति स्वस्थ नहीं मानी जा सकती। सिद्धांत आधारित राजनीति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला होती है।

प्रेग्नेंसी में पत्नी का कैसे रखें ख्याल

मां बनना एक बहुत ही सुखद एहसास है। लेकिन कोई भी महिला इस सुखद और सुंदर पहलू का आनंद तभी उठा सकती हैं जब गर्भावस्था के दौरान वो खुद और उसका बच्चा स्वस्थ रहे। ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जब गर्भवती महिला अपना अच्छे से ख्याल रखे। किन्तु गर्भावस्था के शुरू के तीन महीनों में कई महिलाओं को जी मचलाने या उल्टी आने की शिकायत होती है। इसके अतिरिक्त कुछ महिला उन दिनों बीमार भी पड़ जाती है। लेकिन होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है की उसकी माँ भी स्वस्थ रहे। इसलिए ऐसे में जरुरी है की पति अपनी पत्नी का ख्याल रखे। क्योंकि जब भी किसी लड़की को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है तो वह इस बात को सबसे पहले अपने पति के साथ शेयर करना चाहती है।

सबसे पहले खुद एडजस्ट करें

गर्भवती होने के बाद हर महिला के शरीर में काफी परिवर्तन आ जाता है जिसके चलते दैनिक कार्य रूटीन से नहीं हो पाते है। ऐसे में उन्हें कुछ भी कहने के बजाय कुछ समय के लिए आप खुद एडजस्ट करना सिख जाए ऐसे में आपकी पत्नी परेशान नहीं होगी। जितना हो सके आपको होने वाली मां के कम्फर्ट का ध्यान रखना है। यदि आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा है तो कुछ दिन बाहर ही नाश्ता कर ले।

पत्नी को प्यार दे

गर्भवती होने के बाद अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को देखकर स्त्री बहुत परेशान रहती है। उन्हें ऐसा लगता है की वह गर्भावस्था के दौरान अच्छी नहीं दिखती हैं, अब उनके पति उन्हें प्यार नहीं करेंगे। इसलिए उनका भ्रम दूर करे। उन्हें हर पल जताए की आप उनसे प्यार करते है और वो पहले जितनी ही सुंदर हैं। इसके साथ ही उनका ख्याल भी रखें।

कुछ महत्वपूर्ण बातो का ध्यान रखे

पति कुछ जरुरी बातो की जानकारी रखें जैसे पत्नी को कब कौन सा इंजेक्शन लगना है या फिर चिकित्सक को कब दिखाना है आदि। इसके अतिरिक्त यदि आपकी पत्नी को किसी चीज से एलर्जी है तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा।

उसके खान पान का ख्याल रखे

देखा गया है की ज्यादातर महिलाएं इन दिनों में अपने खान-पान का विशेष ध्यान नहीं रख पातीं है। जिसे चलते उनके शरीर में लौह तत्व की कमी से एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अपनी पत्नी के खान पान का भी ख्याल रखे। चाहे तो कुछ दिन के लिए अपने किसी रिस्तेदार को मदद के लिए बुलाले। गर्भावस्था में स्त्री को हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दाल, अंकुरित अनाज, प्रचुर मात्रा में दूध आदि अवश्य लेना चाहिए।

इन बातो का भी रखे ख्याल

- गर्भावस्था के दौरान अपनी पत्नी के साथ रेगुलर चेकअप पर जाएं। अल्ट्रासाउंड रूम में भी साथ रहें और बच्चे की हरकत को पेट छूकर महसूस करे।
- प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कमर में भयानक दर्द होता है। इसलिए ऐसे में उन पर अधिक काम का बोझ न लादें।
- अपनी पत्नी की भी बात सुनें, उनसे पूछें की उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। उनका ख्याल रखने के साथ साथ अधिकतर समय उनके साथ बिताएं।
- रोमेंटिक बातों के लिए टाइम निकाले, क्योंकि कुछ समय बाद आप दोनों अकेले नहीं रह जाएंगे। फिर शायद नन्हे को संभालने के चक्कर में आप एक दूसरे को ज्यादा वक्त नहीं दे पाए।

आफत न बन जाए आदत

आदत से छुटकारा पाना बेहद मुश्किल होता है। खासतौर पर ऐसी आदतें, जिनमें तनाव को कम करने का गुण होता है, पर सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं, उन्हें छोड़ना और भी मुश्किल होता है। धूम्रपान, तंबाकू और अत्यधिक शराब के सेवन को इनमें शामिल किया जाता है। पर उन आदतों का क्या, जो दिखने में तो सामान्य लगती हैं, पर सेहत पर गंभीर असर डालती हैं?

देर रात स्नैक्स खाना

देर रात कुछ खाने में इतनी बुराई नहीं है, पर फल-सब्जियों या हल्का खाने की बजाए ठंडा पिज्जा, ब्रेड स्लाइस, नूडल्स या तला-भुना खाना सेहत के लिए समस्या पैदा कर सकता है। ऐसे लोग, जिन्हें एसिडिटी की समस्या रहती है, उनके लिए तो देर रात में खाना समस्या को बढ़ा सकता है।

क्या करें: आमतौर पर देर रात में खाना भूख की वजह से कम, बोरियत के कारण अधिक होता है। लोग टीवी या फिल्म देखते हुए आलू चिप्स या सैंडविच आदि खाते हैं। एक शोध के अनुसार, टीवी न देखते समय की तुलना में टीवी या फिल्म देखते समय लोग 44 प्रतिशत अधिक चिप्स खाते हैं। इस आदत से बचने के लिए बेहतर है कि आप टीवी देखते समय कुछ छोटे-छोटे काम कर लें, मसलन किए जाने वाले कार्यों की लिस्ट बनाना, कपड़ों की तह लगाना, ई-मेल चेक करना या अधूरे कामों को पूरा करना आदि। इससे आप कुछ खाने की अपनी इच्छा को दबा सकेंगे।

गलत फिटनेस एक्सेसरीज

यदि आप अपनी फिटनेस को लेकर सजग हैं और नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो अपनी फिटनेस एक्सेसरीज का भी अवश्य ध्यान रखें। गर्मी के दिनों में सामान्य सूती कमीज को पहन कर व्यायाम करना खुजली या त्वचा पर रगड़ उत्पन्न कर देता है। व्यायाम करते समय जूते-जुराब अवश्य पहनें।

क्या करें: सही स्पोर्ट शूज पहनें। ऐसी जगह से जूते खरीदें, जहां स्पोर्ट्स एक्सेसरीज मिलती हों। पसीने को सोखने वाले फेब्रिक से बने कपड़े पहनें। कपड़े आरामदेह या अधिक कसे हुए न हों।

भरपूर नींद न लेना

पर्याप्त नींद न लेना सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। इससे आपकी सक्रियता कम हो जाती है। पर्याप्त नींद की कमी रोग प्रतिरोधी क्षमता को कम कर देती है। महिलाओं का पर्याप्त नींद न लेना हृदय रोगों की आशंका को बढ़ा देता है।

क्या करें: विशेषज्ञों के अनुसार, नींद आहार की तरह है। समय पर सोना चाहिए। सोने से पहले कैफीनयुक्त पदार्थों के सेवन से बचें। शोर और अतिरिक्त रोशनी से दूर रहें।

यदि आप रात को नहीं सो पा रहे हैं तो थोड़ी नींद दोपहर में लें। सोने से पहले टीवी व कंप्यूटर न देखें।

नाखून चबाना

नाखून चबाना एक सामान्य आदत है, जो अक्सर तब देखने को मिलती है, जब व्यक्ति तनाव में होता है। इससे नाखूनों की सामान्य वृद्धि पर तो असर पड़ता ही है, उनकी शेप भी अनियमित हो जाती है। नाखूनों की उचित सफाई न रखने पर उनमें जमा कीटाणु खाने के जरिए पेट में जाकर संक्रमण का कारण बन जाते हैं। नाखूनों की परत के नीचे नुकसानदायक स्टेफिलोकोकस नामक बैक्टीरिया होता है, जो चबाने पर मुंह में चला जाता है। एक शोध के अनुसार, 19 से 29 प्रतिशत युवा वयस्क और 5 प्रतिशत बड़ी उम्र के व्यक्ति नाखून चबाते हैं।

क्या करें : दो से तीन सप्ताह में एक बार किसी प्रोफेशनल से मेनिक्योर करवा सकते हैं। जब आपके नाखून सुंदर लगते हैं तो आप उन्हें चबाना पसंद नहीं करते। नाखून चबाने की इच्छा उत्पन्न होने पर क्रीम या तेल से उनकी मालिश करें या फिर गाजर या सेब जैसी चीजें चबाएं।

डॉक्टर को पूरी बात न बताना

सेहत संबंधी समस्या है तो डॉक्टर के पास जाने से निश्चित तौर पर फायदा मिलता है, पर बातचीत करते समय चिकित्सक को पूरी बात न बताना उपचार के तरीके को बदल सकता है। खासतौर पर मधुमेह या हाइपरटेंशन से पीड़ितों के लिए दवा लेते समय विस्तृत बातचीत जरूरी है।

क्या करें: जब भी डॉक्टर के पास जाएं, बीमारी के लक्षणों और ली जा रही पूर्व दवाओं के बारे में पूरी जानकारी दें। बेहतर होगा कि मिलने से पहले पूरी सूची बना लें, जिसमें एल्कोहल या ली जा रही दवाओं व अन्य बातों की पूरी जानकारी दें।

कान में पिन डालना

कान में हल्का-सा भारीपन होने या फिर खुजली होने पर पहला ध्यान कान की सफाई करने का होता है। आमतौर पर लोग बालों में लगाने वाली पिन, बॉल पेन, पेंसिल आदि को कान में डाल कर कान के भीतर जमी परत को निकालते हैं, जिसे सामान्य शब्दों में मैल कह दिया जाता है।

क्या करें: कान में वेक्स जमा होने का एक बड़ा कारण भोजन को ढंग से चबा कर न खाना है। कान में लगाई जाने वाली एक्सेसरीज जैसे हैडफोन, लंबे समय तक ईयरफोन से भी वेक्स

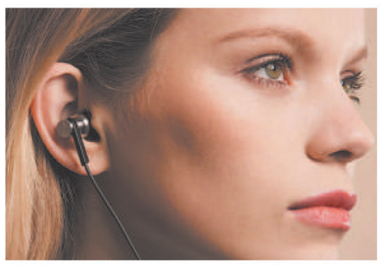

जमा होती है। इनसे बचें।

संगीत का रोग

प्रारंभ में भले ही आप कुछ देर हेडफोन लगा कर तेज आवाज में संगीत सुनते हैं, पर कुछ समय बाद आपके कान को उतनी ही आवाज में सुनने की आदत पड़ जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप तेज से तेज आवाज को ग्रहण करने लगे हैं। पर लंबे समय तक ऐसा करना आपके सुनने की क्षमता में स्थायी दोष उत्पन्न कर सकता है। आपको लगता है कि लगातार कान में कुछ आवाज हो रही है, जिसे टिनिटस कहा जाता है।

क्या करें: मस्तिष्क को धीमी आवाज सुनने के लिए तैयार करें। अपने आईपैड या कार स्टीरियो की आवाज धीमी रखें, इतनी कि दूसरे जो आपसे बात कर रहे हैं, उन्हें चिल्लाना न पड़े।

शाम स्क्रीन के साथ बिताना

सप्ताह में एक-दो बार काम के बाद थियेटर में फिल्म देखना या कुछ देर नियमित टीवी देखना सही हो सकता है, पर हर दिन देर रात तक स्क्रीन के सामने समय बिताना बुरी आदत है। जो लोग अत्यधिक तनाव में रहते हैं या जिनके दोस्तों का नेटवर्क सीमित है, वे अक्सर काम के बाद अकेले समय बिताते हैं। नतीजा देर तक सोफे पर बैठे-बैठे टीवी देखते रहने से शरीर और दिमाग थकता है। शोध कहता है कि सप्ताह में 19 घंटे से अधिक टीवी या बड़े परदे के आगे समय बिताना मोटापे की आशंका 97 प्रतिशत बढ़ा देता है।

क्या करें: विशेषज्ञों के अनुसार, इस आदत से छुटकारा पाने का तरीका है कि टीवी देखते समय कुछ काम करते रहें। सप्ताह में दो-तीन बार कुछ समय दोस्तों के साथ बिताएं। खेलकूद में समय दें।

प्यार करोगे तो मोटे हो जाओगे!

प्रेम होना किसी के लिए भी बेहद अमूल्य बात हो सकती है, लेकिन एक नए सर्वेक्षण के अनुसार मोटापा के लिए भी प्रेम में होना मुख्य कारण हो सकता है। नए सर्वेक्षण में प्रेम के कारण वजन बढ़ाने वाली कई परंपरागत परिस्थितियां बनती हैं, जैसे सहजता से भोजन करना, छुट्टियों में एक-दूसरे के साथ होना या व्यायाम न करना आदि।

सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि प्रेम होने के बाद उनका वजन बढ़ा। इन्हीं व्यक्तियों से ठीक तीन महीने बाद दोबारा पूछे जाने पर उन्होंने स्वीकार किया कि उनके प्रेमी युगल के वजन में भी इजाफा हुआ। सर्वेक्षण में शामिल दो तिहाई लोगों ने स्वीकार किया कि प्रेम होने के बाद उनके और उनके प्रेमी युगल के वजन में भी वृद्धि हुई।

महिलाओं ने स्वीकार

सर्वेक्षणकर्ता एवं डाइट शेफ की पोषण एवं वजन प्रबंधन विशेषज्ञ ने कहा कि सर्वेक्षण में कुछ बहुत रोचक परिणाम सामने आए हैं। यह जानना बहुत चौंकाने वाला है कि प्रेम होने के बाद लोग कितने आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं। सर्वेक्षण में शामिल अधिकतर महिलाओं ने स्वीकार किया कि जब वे अकेली थीं तब जितना भोजना करती थीं उसके मुकाबले साथी के साथ भोजन के दौरान वे थोड़ा ज्यादा भोजन करती हैं।

सर्वेक्षण में शामिल अधिकतर युगलों ने अपनी दिनचर्या में साथ-साथ टीवी देखना, घर में हों तब भी साथ-साथ भोजन करना और अगर बाहर हों तब भी साथ-साथ भोजन करना स्वीकार किया। इससे उनकी दैनिक क्रियाओं की गतिविधियों का पता चलता है।

फार्मा सेक्टर में बेहतर मौके...

फार्मेसी एक ऐसा सेक्टर है, जिसमें मंदी के दौरान भी नौकरी की कोई कमी नहीं होती। करियर के लिहाज से देखें, तो यह एक शानदार सेक्टर है। मौजूदा समय में भारत क्लीनिकल रिसर्च आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में भी ग्लोबल हब बन कर उभर रहा है। ऐसे में अगर आप चिकित्सा और सेहत के क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं तो फार्मेसी में करियर बना कर अपने भविष्य को संवारने का बेहतर मौका मिल सकता है। साइंस विषय के साथ बारहवीं परीक्षा पास करने के बाद दो साल के डी फार्मा कोर्स या चार साल के बी फार्मा कोर्स कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित कई संस्थान, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अंडरग्रेजुएट कोर्स करवाने के अलावा एम फार्मा कोर्स भी करवाते हैं। पहले भारत में फार्मास्युटिकल की पढ़ाई गिने-चुने संस्थानों में ही होती थी, लेकिन तेजी से बढ़ते बाजार और ट्रेंड लोगों की मांग को पूरा करने के लिए अब कई संस्थानों में ऐसे कोर्सेस की शुरुआत हो गई है। छात्र अब बारहवीं के बाद सीधे डिप्लोमा कर सकते हैं। कुछ कॉलेजों में फार्मेसी में फुलटाइम कोर्स संचालित हैं।

स्पेशलाइजेशन के लिए

फार्मा रिसर्च में स्पेशलाइजेशन के लिए एनआईपीईआर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च जैसे संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं। इसके साथ-साथ पीजी डिप्लोमा इन फार्मास्युटिकल एवं हेल्थ केयर मार्केटिंग, डिप्लोमा इन फार्मा मार्केटिंग, एडवांस डिप्लोमा इन फार्मा मार्केटिंग एवं पीजी डिप्लोमा इन फार्मा मार्केटिंग जैसे कोर्स भी संचालित किए जा रहे हैं। इन पाठयक्रमों की अवधि छह माह से एक वर्ष के बीच है। इन पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता बीएससी, बीफार्मा अथवा डीफार्मा निर्धारित की गई है।

व्यक्तिगत योग्यता

यदि आप फार्मेसी की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी साइंस और खासकर लाइफ साइंस तथा दवाइयों के प्रति दिलचस्पी होनी चाहिए। इससे जुड़े रिसर्च के क्षेत्र में काम करने के लिए आपकी दिमागी विश्लेषण क्षमता बेहतर हो और आपकी शैक्षणिक बुनियाद भी अच्छी होनी चाहिए। यदि आप इससे जुड़े मार्केटिंग क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जरूर बेहतर होनी चाहिए। डीफॉर्मा और बीफॉर्मा कोर्स में दवा के क्षेत्र से जुड़ी उन सभी बातों की थ्योरेटिकल और प्रायोगिक जानकारी दी जाती है जिनका प्रयोग आमतौर पर इस उद्योग के लिए जरूरी होता है। इसके साथ फार्माकोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लीनिकल फार्मेसी, फॉर्मास्यूटिकल, हेल्थ एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी आदि विषयों की जानकारी दी जाती है।

रिसर्च एंड डेवलपमेंट

भारत आज फार्मास्युटिकल्स के क्षेत्र में काफी तेजी के आगे बढ़ रहा है। वैसे, इस क्षेत्र का दायरा भी काफी व्यापक है। यहां नई-नई दवाइयों की खोज व विकास संबंधी कार्य किया जा सकता है। आरएंडडी क्षेत्र को जेनेरिक उत्पादों के विकास, एनालिटिकल आरएंडडी, एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्युटिकल

कुछ प्रमुख संस्थान

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पंजाब
- आचार्या एंड बीएम रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मासी, बंगलुरु
- कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी, दिल्ली विश्वविद्यालय
- गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा
- बांबे कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी, मुंबई
- गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, केरल
- बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पिलानी
- बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
- राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, बेंगलुरु
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़

इन्ग्रेडिएंट्स या बल्क ड्रग आरएंडडी जैसी श्रेणियों में बांटा जा सकता हैं। इन सबका अपना सुपर-स्पेशलाइजेशन है।

ड्रग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर

यह इस इंडस्ट्री की एक बेहद अहम शाखा है, जो स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराती है। आप चाहें, तो इस क्षेत्र में मॉलिक्युलर बॉयोलॉजिस्ट, फार्मेकोलॉजिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट या मेडिकल इंवेस्टिगेटर बनकर अपना भविष्य संवार सकते हैं। मॉलिक्युलर बॉयोलॉजिस्ट जीन संरचना के अध्ययन और मेडिकल व ड्रग रिसर्च संबंधी मामलों में प्रोटीन के इस्तेमाल का अध्ययन करता है, जबकि फार्मेकोलॉजिस्ट का काम इंसान के अंगों व ऊतकों पर दवाइयों व अन्य पदार्थों के प्रभाव का अध्ययन करना होता है। इसी तरह टॉक्सिकोलॉजिस्ट दवाओं के घातक प्रभाव को मापने के लिए अलग-अलग परीक्षण करता है।

मेडिकल इंवेस्टिगेटर

नई दवाइयों के विकास व टेस्टिंग की प्रक्रिया से जुड़ा होता है। मानव जैविकी और दवाइयों संबंधी अपने बैकग्राउंड के कारण वे इसकी रिसर्च प्रक्रिया के लिहाज से बेहद अहम होते हैं। हॉस्पिटल पर दवाइयों और चिकित्सा संबंधी अन्य सहायक सामग्रियों के भंडारण, स्टॉकिंग और वितरण का जिम्मा होता है, जबकि रिटेल सेक्टर में फार्मासिस्ट को एक बिजनेस मैनेजर की तरह काम करते हुए दवा संबंधी कारोबार चलाने में समर्थ होना चाहिए।

क्लिनिकल रिसर्च

जब कोई नई दवा लॉन्च करने की तैयारी होती है, तो दवा लोगों के लिए कितनी सुरक्षित और असरदार है, इसके लिए क्लिनिकल ट्रॉयल होता है। भारत की जनसंख्या और यहां उपलब्ध सस्ते प्रोफेशनल की वजह से क्लिनिकल का कारोबार तेजी से फलने-फूलने लगा है। इस क्षेत्र में हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय जगत की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। आज देश में कई विदेशी कंपनियां क्लिनिकल रिसर्च के लिए आ रही हैं। दवाइयों की स्क्रीनिंग संबंधी काम में नई दवाओं या फॉर्मुलेशन का पशु मॉडलों पर परीक्षण करना या क्लिनिकल रिसर्च करना शामिल है जो इंसानी परीक्षण के लिए जरूरी है।

क्वालिटी कंट्रोल

फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री का यह एक अहम कार्य है। नई दवाओं के संबंध में अनुसंधान व विकास के अलावा यह सुनिश्चित करने की भी जरूरत होती है कि इन दवाइयों के जो नतीजे बताए जा रहे हैं, वे सुरक्षित, स्थायी और आशा के अनुरूप हैं।

रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट

जिस तरह डॉक्टरों को प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, उसी तरह इन्हें भी फार्मेसी में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस चाहिए। उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए एक टेस्ट पास करना होता है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस विषय में ट्रेनिंग के लिए 'फार्मा डी' नामक एक छह साल का कोर्स शुरू किया है।

ब्रांडिंग एंड सेल्स

फार्मेसी की पृष्ठभूमि से जुड़ा कोई प्रोफेशनल, एमबीए डिग्रीधारी और यहां तक कि साइंस की डिग्री प्राप्त करने वाला शख्स भी सेल्स एंड मार्केटिंग में करियर बना सकता है। फार्मास्युटिकल सेक्टर में मार्केटिंग की काफी अहम है। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स उत्पाद की बिक्री के अलावा बाजार की प्रतिस्पर्धा पर भी निगाह रखते हुए इस बात का निर्धारण करते हैं कि किस उत्पाद के लिए बाजार में ज्यादा संभावनाएं हैं। इसी के मुताबिक रणनीति तैयार की जाती है। इस क्षेत्र में काम करने के लिए यदि आपके पास बीफार्मा के साथ साथ एमबीए की भी डिग्री है तो सोने पर सुहागा वाली बात होगी। प्रशिक्षित पेशेवर की मांग दुनिया की बेहतरीन फॉर्मास्यूटिकल कंपनियां भारत में अपना कारोबार कर रही हैं। इनके अलावा, रैनबैक्सी, एफडीसी, कैडिला, शिपला, डॉ. रेड्डीज, डाबर, ल्यूपिन आदि कंपनियां भारत में व्यवसायरत हैं। इस क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों की काफी मांग है।

यहां हैं मौके

नर्सिंग होम, अस्पतालों और कंपनियों में आपके लिए नौकरी के अवसर हैं। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्म्ड फोर्सेज में भी काफी संभावनाएं हैं। बीफॉर्मा करने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, एनालिस्ट कैमिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्लीनिकल रिसर्च आउटसोर्सिंग सेक्टर में भी आपके लिए कई अवसर मौजूद हैं। जिस तरह से मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है और दवाइयों की खपत बढ़ीं हैं।

जेरियाट्रिक्स केयर बन कर सकते हैं चाहत पूरी

अगर आप सेवा के जुड़े क्षेत्र में कॅरियर बनाना चाहते हैं और साथ में अच्छी कमाई भी करना चाहते हैं कि जेरियाट्रिक्स केयर बन अपनी चाहत पूरी कर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम का संचालन भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय करता है। इसका मकसद युवक-युवतियों को बुजर्गों की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना है। पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ी हैं। दरअसल बुजर्गों की सेवा के लिए इस क्षेत्र में दक्ष लोगों की जरूरत को काफी पहले से महसूस किया जा रहा था।

इस जरूरत को ध्यान में रखकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने जेरियाट्रिक्स केयर पाठ्यक्रम की शुरुआत की जिसके तहत बुजुर्गों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया जाता है। इस पाठ्यक्रम में मूल रूप से विद्यार्थियों को समुदाय के अंदर वृद्ध लोगों की स्थित, एकल और संयुक्त परिवारों के गुण-दोष, सामाजिक सुरक्षा संबंधी उपाय, वृद्धावस्था में मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिति को समझने, पुनर्वास के अलावा उनकी समस्याओं को निपटाना, उनकी पोषाहार संबंधी जरूरतों की जानकारी और आहार प्रबंधन और मनोविज्ञान के अलावा वृद्धावस्था संबंधी देखभाल के आधारभूत सिद्धांतों की जानकारी दी जाती है। इस पाठ्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को घर-घर जाकर वृद्धों की समस्याओं पर रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है।

अपार संभावनाएं

इस क्षेत्र में हाल के दिनों में अपार संभावनाएं उभरी हैं। पीजी डिप्लोमाधारी अभ्यार्थी किसी सरकारी, गैर सरकारी, कॉरपोरेट क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थाओं में अच्छे पद पर कार्य कर सकता है। इसके अलावा गृह देखभाल कर्ता, उपचार सहायक, शारीरिक चिकित्सा सहायक, परियोजना निदेशक, कार्यक्रम अधिकारी, कल्याण अधिकारी बनकर भविष्य संवार सकते हैं।

प्रमुख संस्थान

- डॉ. रेड्डी हैरिटेज फाउंडेशन, हैदराबाद।
- कलकत्ता मैट्रोपोलिटेन इंस्टीट्यूट ऑफ जिरानहोलॉजी, कोलकाता।
- न्यू इंटिग्रेटेड रूरल मैनेजमेंट एजेंसी, इम्फाल।
- राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, आरके पुरम, नई दिल्ली।

तीन कोर्स

बुजुर्गों की देखभाल संबंधी प्रमुख तौर पर तीन कोर्स चलाए जाते हैं। जिसमें तीन महीने और 6 महीने का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और पीजी डिप्लोमा कोर्स शामिल है। तीन माह का कोर्स खासतौर से समाजसेवी संस्थाओं के लिए है जो देश में बुजुर्गों की देखभाल और उनके लिए कार्य करती हैं। पीजी डिप्लोमा कोर्स का मुख्य उद्देश्य समर्पित व्यक्तियों की एक टीम तैयार करना होता है। पीजी डिप्लोमा कोर्स में इस क्षेत्र से संबंधित गहन अध्ययन कराया जाता है जिसमें थ्योरी स्तर प्रैक्टिकल और परियोजना कार्य के अलावा इंटर्निशप और सेमिनार प्रस्तुति भी सिखाई जाती है।

ऐसे होता है दाखिला

इन सभी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा देना पड़ती है। पीजी डिप्लोमा कोर्स में नामांकन के लिए उम्मीदावार को किसी भी संस्थान से समाज विज्ञान, समाज कार्य, मानव विज्ञान, परिचर्चा या गृहविज्ञान में स्नातक होना आवश्यक है। साथ ही अभ्यर्थी की उम्र किसी भी हालत में 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए।

वहीं वृद्धावस्था देखभाल संगठनों में कार्यरत या वृद्धावस्था सेवा क्षेत्र में प्रमाणपत्र प्राप्त उम्मीदवारों, सामाजिक कार्यकर्ता, काउंसलर, स्वास्थ्य कर्मी और नर्सिंग के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।

जबकि 3 और 6 महीने के प्रमाणपत्र कोर्स के लिए उम्मीदवार का मैट्रिक पास होना आवश्यक है साथ ही उसकी आयु 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को साक्षात्कार से भी गुजरना पड़ता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

गद्दारों को टिकट देना गलती थी, जनता से माफी मांगता हूं

मुंबई। मुंबई के भांडुप में बागी सांसद संजय दिना पाटिल के गढ़ में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बागी नेताओं और बीजेपी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने रैली में जुटी भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, %मेरे सामने सिर्फ शिवसैनिक नहीं, बल्कि जलती हुई मशालें खड़ी हैं. उद्धव ठाकरे ने कहा, %मैं गद्दारों और उनके आकाओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इन मशालों को फिर से जला दिया. मैंने पार्टी स्थापना दिवस पर जो वादा किया था, अब उस पर अमल शुरू कर दिया है. जहां-जहां विश्वासघात हुआ है, वहां-वहां मैं खुद जाकर मतदाताओं से माफी मांग रहा हूं. जनता ने पाला बदलने वाले सांसदों को शिवसेना और मशाल चुनाव चिह्न देखकर चुना था. उन्हें उम्मीदवार बनाना हमारी गलती थी और उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं. उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना को कई बार तोड़ने और कमजोर करने की कोशिश की गई।

उत्तराखंड में नागरासू गुरुद्वारा विवाद गहराया

उत्तराखंड। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के नागरासू स्थित गुरुद्वारे में बीते 24 घंटे से जारी विवाद गहराता जा रहा है. कुछ निहंग गुरुद्वारे की छत पर डटे हैं, जबकि प्रबंधक को बंधक बनाए जाने के आरोप भी सामने आए हैं. फिलहाल प्रशासन मौके पर मौजूद है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है.जानकारी के अनुसार, गुरुद्वारा प्रबंधन और निहंग यात्रियों के बीच विवाद के बाद कुछ निहंग गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए और परिसर में डटे रहे. आरोप है कि इस दौरान सेवादारों के साथ मारपीट और अभद्रता की गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और आईटीबीपी की टीमें मौके पर पहुंच गईं. हालात को नियंत्रित करने के लिए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने रुद्रप्रयाग और श्रीनगर क्षेत्रों में एहतियातन इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं, ताकि सोशल मीडिया के जरिए किसी तरह की अफवाह न फैल सके।

मोदी की तारीफ को लेकर घर में घिरे थरूर

नई दिल्ली। कांग्रेस और शशि थरूर के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है. कांग्रेस ने थरूर पर तंज कसा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए उनका प्यार अब इतना बढ़ गया है कि वो ऐसी बातें भी सुन लेते हैं, जो पीएम मोदी ने कभी बोली ही नहीं. ये पूरा मामला भारतीय नाविकों की सुरक्षा से जुड़े एक बयान को लेकर शुरू हुआ है. थरूर ने कहा था कि पीएम मोदी ने अपनी पब्लिक और प्राइवेट बातचीत दोनों में भारतीय नागरिक नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था. थरूर के मुताबिक पीएम मोदी का कहना था कि युद्ध के समय कमर्शियल जहाजों पर काम करने वाले सिविलियन नाविकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. थरूर ने कहा था,ये बताना जरूरी है कि युद्ध के समय कमर्शियल जहाजों पर मौजूद सिविलियन नाविक लड़ाई के निशाने पर नहीं होने चाहिए. वो सैनिक नहीं हैं और यही बात पीएम मोदी ने कही।

कही जांच रिपोर्ट न हो जाए चोरीः अखिलेश

लखनऊ। अयोध्या राम मंदिर चंदा घोटाले की जांच कर रही एसआईटी पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा व्यंग्य किया है. उन्होंने विशेष जांच दल को सचेत करते हुए तंज कसा है कि वह ध्यान रखें कि कहीं इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर चल रही चंदा चोरी की बहस के बीच एसआईटी की कार्यप्रणाली पर बड़ा तंज कसा है. उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में सीधे तौर पर जांच एजेंसी को आगाह किया कि एसआईटी को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, कहीं जांच की रिपोर्ट ही गायब या चोरी न हो जाए. अखिलेश ने आगे लिखा कि फिर कहेंगे 15 दिन और इंतजार कर लो. दिन इसलिए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं. इससे पहले वीएचपी के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अलोक कुमार ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा था कि वो राम मंदिर के मुद्दे को चुनावी हथियार बना रहे हैं।

काकोली ने महुआ को सुनाई खरी-खरी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और बागी नेताओं के बीच चल रही खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है. पार्टी की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने सीनियर टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा के बयान पर तीखा पलटवार किया है. काकोली घोष ने कहा कि बंगाल की जनता टीएमसी की राजनीति और उनके नैरेटिव को नकार चुकी है. काकोली घोष ने महुआ मोइत्रा के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने बागी सांसदों के सियासी भविष्य पर सवाल उठाए थे. तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद काकोली घोष ने कहा, यह सिर्फ आपकी मनगढ़ंत सोच है. आप अजीब और हकीकत से दूर वाली सोच में जी रही हैं. बंगाल की जनता ने आपको हरा दिया है और उनका जनादेश साफ तौर पर आपकी अराजकता के खिलाफ है. कोई भी आपको या आपकी बातों को स्वीकार नहीं कर रहा है. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्र ने मीडिया से बात करते हुए बागी सांसदों पर तंज कसा था. इसके साथ ही उन्होंने इशारा किया था कि बीजेपी अपना टारगेट पूरा करने के बाद इन लोगों को बाहर फेंक देगी।

बागियों को आदित्य ठाकरे ने बताया बिकाऊ

वफादारी पर भी सवाल, कहा- लालच में विचारधारा छोड़ी

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने सोमवार को पार्टी के बागी सांसदों की आलोचना करते हुए उन पर आरोप लगाया कि वे अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ज़्यादा निजी लालच को अहमियत देते हैं। उन्होंने इन सांसदों को बिकाऊ करार दिया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के समर्थन से चुने गए इन सांसदों ने उन विचारधाराओं को छोड़ दिया है, जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिए वे चुने गए थे।

शिवसेना (यूबीटी) में चल रहे राजनीतिक संकट और तथाकथित ऑपरेशन टाइगर के तहत कई सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की खबरों के बीच, ठाकरे ने कहा कि बागी सांसदों के काम यह दिखाते हैं कि उनकी वफादारी और प्रतिष्ठा बिकने के लिए है। उन्होंने सरकार पर राजनीतिक मकसद के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी बदलने वाले लालची सांसदों, आप पहले से भी ज़्यादा मज़बूती से ये बातें साबित करते हैं- 1) आपकी वफ़ादारी और आपकी साख बेशर्मी से बिकने के लिए है 2) सरकार पक्षपाती है और जनता के पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक फ़ंड के तौर पर करती है।

उन्होंने दावा किया कि इन सांसदों के चुनाव क्षेत्रों के वोटरों ने खास तौर पर एनडीए उम्मीदवारों और उनकी विचारधाराओं के खिलाफ वोट दिया था, जिन्हें इन सांसदों ने अब लालच में आकर छोड़ दिया है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग अभी पाला बदल रहे हैं, वे सभी एनडीए के खिलाफ एमवीए और इंडिया गठबंधन के मंच से चुने गए थे। उन सभी के लिए शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने प्रचार किया था - हर एक ने सभी पार्टियों और सहयोगियों के

नेताओं से रैलियां करने को कहा था। वे यह बेतुकी बात भी नहीं कह सकते कि 'इससे अलग हो गए और उससे गठबंधन कर लिया' या ऐसा-वैसा किया। आपके चुनाव क्षेत्रों में वोटरों ने एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दिया था, और इंडिया गठबंधन जिन मूल्यों के लिए खड़ा है, उसके समर्थन में वोट दिया था। बस यह मान लीजिए कि आपके लालच ने आपको रातों-रात, बिना किसी शर्म के, यह सब छोड़ने पर मजबूर कर दिया।

इसके अलावा, शनिवार को शिवसेना (यूबीटी) ने उन सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जो अनुपस्थित थे। इसमें दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने की चेतावनी दी गई। लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक अनिल देसाई द्वारा भेजे गए इस नोटिस में सांसदों को निर्देश दिया गया कि वे संसदीय दल की एक अहम बैठक से अपनी अनुपस्थिति के बारे में 24 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण दें।

हिंदुत्व की राह से भटके उद्धव ठाकरे भाजपा ने टूटने की बताई वजह

चेन्नई। शिवसेना यूबीटी अपने सांसदों के संभावित दलबदल को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। अब इस पर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की राह से भटक गए हैं और इसी वजह से उनकी पार्टी में टूट हुई है। भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना, हिंदुत्व की राह से भटकी और कांग्रेस की पिछलग्गू पार्टी बन गई। इसके चलते मूल शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एकत्रित हुई है। आज शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ेंगे। असली शिवसेना वही है जो हिंदुत्व की विचारधारा को मानती है और जिसके पास सांसद और विधायक हैं।

राम मंदिर चंदा मामले विपक्ष के आरोप पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा, तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के पानी के लिए भारत से युद्ध करने वाले बयान पर आरपी सिंह ने कहा, पानी और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते हैं। अगर आतंकी भेजते रहेंगे तो भारत से एक बूंद भी पानी नहीं भेजा जाएगा। अगर अगली बार युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का नाम दुनिया से मिट जाएगा।

राजस्थान में मस्जिदों के ध्वस्तीकरण पर असदुद्दीन ओवैसी ने रोक लगाने की मांग की है। इस पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा, कहीं पर भी मस्जिद नहीं गिराई जा रही है, ओवैसी जानबूझकर अफवाह फैला रहे हैं। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालातों की तारीफ करने पर उनका पार्टी के अंदर आलोचना शुरू हो गई है। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता ने कहा, जो दिखता है, शशि थरूर वही बोलते हैं। आज कश्मीर विकसित भारत का हिस्सा बनकर आगे बढ़ रहा है, इसलिए शशि थरूर ने सही कहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब में सरकार बनाने वाले बयान पर आरपी सिंह ने कहा, इस बार पंजाब में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। पिछली बार 18.56 फीसदी वोट भाजपा को मिले थे। इस बार 40 फीसदी वोट प्राप्त करने का लक्ष्य है।

ग्रेट निकोबार परियोजना पर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल

नई दिल्ली। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को लेकर लगातार सवाल उठा रहे कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल को पत्र लिखा है। इस पत्र में जयराम रमेश ने परियोजना के तहत बनने वाले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के विकास को लेकर कई स्पष्टीकरण मांगे हैं। पत्र में जयराम रमेश ने ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के विकास के लिए निजी कंपनी की भागीदारी के लिए निविदाएं जारी करने की समय-सीमा और निजी कंपनी के चयन की प्रक्रिया की जानकारी मांगी है।

उन्होंने यह भी पूछा कि परियोजना में निजी क्षेत्र की न्यूनतम हिस्सेदारी 55 प्रतिशत निर्धारित की गई है, तो क्या 100 प्रतिशत निजी स्वामित्व की अनुमति होगी, या फिर सार्वजनिक संस्थाओं के लिए भी न्यूनतम हिस्सेदारी तय की गई है? जयराम रमेश ने प्रोजेक्ट से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर चिंता भी जताई।

कांग्रेस नेता ने कहा कि समिति के रिकॉर्ड के अनुसार परियोजना के विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) में कम से कम 55 प्रतिशत हिस्सेदारी किसी भारतीय स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली इकाई के पास होनी चाहिए।

उन्होंने तीन प्रमुख सवाल उठाए-1. क्या 55 प्रतिशत न्यूनतम निजी हिस्सेदारी का मतलब है कि परियोजना में 100 प्रतिशत निजी स्वामित्व की अनुमति होगी? 2. क्या बंदरगाह क्षेत्र में स्वामित्व का विविधीकरण सुनिश्चित किया जाएगा या फिर हवाईअड्डों की तरह ऐसी स्थिति बनने दी जाएगी, जहां एक ही निजी कंपनी अधिकांश परिसंपत्तियां हासिल कर ले? 3. जब पीपीपीएसी ने परियोजना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) अनुदान देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, तो क्या मंत्रालय अपने बजट से पूंजीगत सहायता उपलब्ध कराएगा?

रमेश ने मंत्री से यह भी आग्रह किया कि वे निविदा जारी करने और निजी भागीदार के अंतिम चयन की संभावित समय-सीमा साझा करें। जयराम रमेश इससे पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी कई पत्र लिख चुके हैं। इन पत्रों में उन्होंने परियोजना से होने वाले संभावित पर्यावरणीय विनाश और पारिस्थितिकीय प्रभावों को लेकर चिंता जताई है।

बागी टीएमसी सांसदों की सदस्यता रद्द करें स्पीकर

सौगत रॉय ने बजट सत्र से पहले सरकार पर उठाए सवाल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति उथल-पुथल के बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने बागी सांसदों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इस दौरान सौगत रॉय के साथ चार अन्य सांसद भी इस बैठक में शामिल थे। करीब एक घंटे तक चली इस बातचीत में टीएमसी नेताओं ने बागी सांसदों के कदम को नियम के खिलाफ बताया।

सौगत रॉय ने स्पीकर से कहा कि जो सांसद अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं, उन्हें कानून के हिसाब से लोकसभा से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि इन बागी सांसदों ने किसी दूसरी पार्टी के साथ विलय (मर्जर) के नियमों का पालन नहीं किया है। इसलिए उनके नए गुट को आधिकारिक मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। सौगत रॉय को उम्मीद है कि स्पीकर संविधान के अनुसार फैसला लेंगे।

पश्चिम बंगाल बजट सत्र से पहले सौगत रॉय ने भाजपा सरकार पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह देखना चाहते हैं कि भाजपा सरकार घाटे के कर्ज और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से कैसे निपटती है।

इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब टीएमसी के 28 में से 20 सांसदों ने बगावत कर दी। इन सांसदों ने नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल होने और संसद में एनडीए का समर्थन करने का फैसला किया है। बागी सांसदों ने स्पीकर से मिलकर सदन में अलग बैठने की जगह भी मांगी। उनका दावा है कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है।

टीएमसी नेतृत्व इस कदम से बेहद नाराज है। पार्टी नेता कुणाल घोष ने इसे मतदाताओं के साथ बड़ा धोखा बताया। उन्होंने कहा कि ये सांसद ममता बनर्जी के चेहरे और टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर आए थे। अब एनडीए का साथ देना उन लोगों के साथ विश्वासघात है जिन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट दिया था। वहीं, मदन मित्रा ने तंज कसते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का जाना बताता है कि दाल में कुछ काला है।

दूसरी तरफ, भाजपा ने इसे टीएमसी का अंदरूनी संकट बताया है। भाजपा का कहना है कि टीएमसी को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने भीतर झांकना चाहिए। फिलहाल सबकी नजरें लोकसभा स्पीकर के फैसले पर टिकी हैं कि वह इन सांसदों की सदस्यता पर क्या रुख अपनाते हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

फीफा वर्ल्ड कप में मिश्र की ऐतिहासिक जीत

न्यूयॉर्क। मोहम्मद सालाह ने फीफा वर्ल्ड कप में धीमी शुरुआत के बाद शानदार खेल दिखाया और मिस्र को वैंकूवर के बीसी प्लेस में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ जीत दिलाई। यह इस बड़े मंच पर उनकी पहली जीत थी। 1934 में फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार खेलने के 92 साल बाद, मिस्र ने ऑल व्हाइट्स (न्यूज़ीलैंड टीम) को 3-1 से हराकर अपनी शानदार जीत हासिल की। इस जीत से ग्रुप जी से नॉकआउट में पहुंचने की उनकी उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।

मिस्र ने अपने पहले मैच में बेल्जियम के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला था, लेकिन सालाह की खराब शुरुआत ने फ़राओ (मिस्र की टीम) के साथ उनके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए थे। हालांकि, रविवार को उन्होंने एक गोल किया और एक गोल करने में मदद की, जिससे उनकी टीम ने 50,000 से ज़्यादा दर्शकों के सामने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत हासिल की। कीवी टीम ने तब सबको चौंका दिया जब फिन सुरमैन ने टिम पेन के कॉर्नर पर हेडर मारकर 15वें मिनट में अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दिया। दूसरे हाफ में होसाम हसन की टीम ने वापसी की; 58वें मिनट में मुस्तफा ज़िको ने मोहम्मद हनी के क्रॉस पर हेडर से गोल किया। इसके बाद सलाह ने ज़िको के साथ वन-टू पासिंग गेम खेला और निचले कोने में शॉट मारकर मिस्र को बढ़त दिला दी। 82वें मिनट में सलाह ने सब्स्टीट्यूट ट्रेज़ेगुएट को कॉर्नर पर असिस्ट दिया, जिस पर अल अहली के विंगर ने हेडर से गोल करके बढ़त को दोगुना कर दिया। मिस्र अब नॉकआउट में अपनी जगह पक्की करने और ग्रुप में टॉप पर रहने के लिए तैयार है। वे पहले से ही चार पॉइंट के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि ईरान दूसरे और बेल्जियम तीसरे स्थान पर है। इस हार के बाद न्यूज़ीलैंड चौथे स्थान पर बना हुआ है और वे अपनी पहली वर्ल्ड कप जीत की तलाश में हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 291 अंक उछला निफ्टी 24,100 के पार

नईदिल्ली। आईटी और फार्मा शेयरों में खरीदारी तथा कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट के चलते सोमवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में निफ्टी 50 करीब 90 अंक यानी 0.37 फीसदी की बढ़त के साथ 24,102.90 पर बंद हुआ। वहीं, सेंसेक्स 291.17 अंक यानी 0.38 फीसदी चढ़कर 77,094.07 पर पहुंच गया। निफ्टी 50 में सिप्ला, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज करने वाले शेयर रहे। वहीं, व्यापक बाजार की बात करें तो निफ्टी मिडकैप 0.34 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 0.60 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए। सेक्टोरल इंडेक्स में आईटी, फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरी ओर, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में कमजोरी देखने को मिली।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता का निर्णायक दौर

नई दिल्ली। भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में इस सप्ताह महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में 23 से 24 जून तक दो दिन वार्ता करेंगे। इससे पहले दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के बीच 2 से 4 जून तक नई दिल्ली में विस्तृत बातचीत हुई थी। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, मंत्रीस्तरीय वार्ता का मुख्य उद्देश्य व्यापार समझौते के ढांचे को अंतिम रूप देना है। सरकार को उम्मीद है कि अगले महीने के मध्य तक समझौते के पहले चरण को लागू किया जा सकता है। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है, जब अमेरिका ने फरवरी 2026 में लगाए 10% अस्थायी अतिरिक्त आयात शुल्क की अवधि 24 जुलाई को समाप्त होने वाली है।

जापान ने भारत में बड़ा दांव लगाने का बनाया प्लान

नईदिल्ली। जापान की अर्थव्यवस्था और उद्योग जगत तेजी से बदलते सामाजिक हालातों के बीच नई रणनीतियां अपना रहे हैं। देश में लगातार घटती आबादी, बढ़ती बुजुर्ग जनसंख्या और सिकुड़ते घरेलू बाजार ने जापानी कंपनियों को विदेशी बाजारों की ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया है। इसी क्रम में भारत जापान के खाद्य और कृषि उद्योग के लिए सबसे आकर्षक बाजार बनकर उभरा है। जापान के कृषि, वानिकी और मत्स्य मंत्रालय के उपमहानिदेशक केन सासाजी के अनुसार भारत जापानी खाद्य उत्पादों के लिए एक विशाल और संभावनाओं से भरा बाजार है। एक बार मजबूत ढांचा तैयार हो जाने के बाद कारोबार लगातार बढ़ेगा। उनके मुताबिक भारत में केवल खाद्य उत्पाद ही नहीं बल्कि कृषि मशीनरी, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेशन सुविधाएं, सुरक्षित परिवहन प्रणाली, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी भारी संभावनाएं मौजूद हैं।

सैमसंग को पछाड़ एसके हायनिक्स ने रचा इतिहास

नईदिल्ली। टेक इंडस्ट्री में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जिसने सबको चौंका दिया है। एसके हायनिक्स ने मार्केट कैप के मामले में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 26 सालों में यह पहली बार है जब सैमसंग से उसका नंबर वन का ताज छिना है। सोमवार को शेयर बाजार में कारोबार के दौरान एसके हायनिक्स के शेयरों में 5.7% की तेजी आई, जिसके बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 2,082.5 ट्रिलियन वॉन (करीब 1.35 ट्रिलियन डॉलर) पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में केवल 0.4% की मजबूती रही, जिससे उसका मार्केट कैप 2081.3 ट्रिलियन वॉन रह गया। विश्लेषकों का मानना है कि एआई से जुड़ी तकनीकों की तेज मांग ने एसके हायनिक्स को जबरदस्त बढ़त दिलाई है।

होर्मुज खुलने से सस्ता होगा तेल, महंगाई घटेगी और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा सहारा

कांतिलाल मांडोत

ईरान और अमेरिका के बीच 110 दिनों तक चले तनाव और संघर्ष के बाद हुए शांति समझौते ने पूरी दुनिया को राहत की सांस लेने का अवसर दिया है। इस समझौते का सबसे सकारात्मक प्रभाव भारत पर पड़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में भारत में महंगाई की दर 0.5 से 0.8 प्रतिशत तक घट सकती है। इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में भी राहत मिलने की संभावना है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लौटने से भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है।

भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में पश्चिम एशिया में किसी भी प्रकार का तनाव सीधे भारतीय बाजार और आम लोगों की जेब पर असर डालता है। युद्ध के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा आने से तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई थी और कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थीं। अब ईरान द्वारा होर्मुज को बिना शर्त खोलने की घोषणा के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति सामान्य होने लगी है, जिससे ऊर्जा कीमतों पर दबाव कम होगा।

युद्ध के दौरान भारतीय बास्केट के कच्चे तेल का भाव 69 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 157 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। हालांकि अब यह घटकर लगभग 78 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया है, लेकिन फिर भी युद्ध पूर्व स्तर से करीब 14 प्रतिशत अधिक है। इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शांति प्रक्रिया स्थायी रहती है तो अगले कुछ महीनों में तेल की कीमतों में और कमी आ सकती है। इसका सीधा लाभ भारतीय उपभोक्ताओं को मिलेगा।

महंगाई नियंत्रण की दिशा में यह

समझौता महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कम होने से परिवहन लागत घटेगी। परिवहन सस्ता होने का असर खाद्यान्न, सब्जियों, फल, दूध, निर्माण सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर दिखाई देगा। इससे बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर दबाव कम होगा और आम परिवारों के घरेलू बजट को राहत मिलेगी।

रसोई गैस की कीमतों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। युद्ध के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 942 रुपये तक पहुंच गए थे। ऊर्जा आपूर्ति सामान्य होने के बाद इन कीमतों में कमी की संभावना बढ़ गई है। इससे विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों को राहत मिलेगी।

भारत के लिए इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू ऊर्जा सुरक्षा भी है। ईरान पर लगे आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध हटने की स्थिति में भारत के लिए वहां से सीधे तेल और गैस खरीदने का मार्ग फिर से खुल सकता है। इससे भारत को तेल आयात के अधिक विकल्प मिलेंगे और वह बेहतर कीमतों पर ऊर्जा खरीद सकेगा। ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा।

चाबहार बंदरगाह को लेकर भी भारत के लिए यह समझौता बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत ने इस रणनीतिक परियोजना में लगभग 1400 करोड़ रुपये का निवेश किया है। ईरान पर प्रतिबंधों के कारण इस परियोजना की संभावनाएं सीमित हो गई थीं, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने से चाबहार बंदरगाह भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक व्यापारिक पहुंच का प्रमुख केंद्र बन सकता है। इससे भारत के निर्यात और क्षेत्रीय व्यापार को नई गति मिलेगी।

खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीयों के लिए भी यह समझौता राहत लेकर आया है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान सहित खाड़ी क्षेत्र में लगभग 95 लाख भारतीय काम करते हैं। युद्ध और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण उनकी नौकरियों तथा आय पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। शांति स्थापित होने से रोजगार की स्थिरता बनी रहेगी और भारत को मिलने वाली विदेशी मुद्रा भी सुरक्षित रहेगी। युद्ध के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

सेवा, सुशासन और जनकल्याण के 12 वर्ष

वित्त मंत्री चौधरी ने प्रबुद्धजनों से किया संवाद

■ विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों, शिक्षाविद् एवं अधिवक्ता का किया सम्मान

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, विकास और जनकल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संचालित 'विशेष जनसंपर्क अभियान' के अंतर्गत वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने रायगढ़ के विभिन्न प्रबुद्ध एवं सम्मानित नागरिकों से आत्मीय मुलाकात कर संवाद किया।

अभियान के तहत वित्त मंत्री श्री चौधरी ने वरिष्ठ चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉ. केदारनाथ पटेल से मुलाकात कर उनके अनुभवों एवं सामाजिक योगदान पर चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने शॉल एवं श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया तथा रामचरितमानस की प्रति भेंट की।

इसी क्रम में वित्त मंत्री ने रायगढ़ के डॉ. रूपेन्द्र पटेल से आत्मीय भेंट कर उन्हें शॉल एवं रामचरितमानस की प्रति भेंट करते हुए सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि समाज के प्रबुद्ध नागरिकों का मार्गदर्शन और अनुभव विकास यात्रा को नई दिशा प्रदान करता है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने अधिवक्ता श्री सुभाष कुमार नंदे से भी सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने शॉल एवं श्रीफल भेंट कर उनका अभिनंदन किया तथा रामचरितमानस की प्रति भेंट की।श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 12 वर्षों का कार्यकाल सेवा, सुशासन, विकास और जनभागीदारी का प्रतीक रहा है। इन वर्षों में गरीब कल्याण, आधारभूत संरचना, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। विशेष जनसंपर्क अभियान का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच पहुंचकर संवाद स्थापित करना तथा जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी साझा करना है।

इस दौरान सभी सम्मानित नागरिकों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों की सराहना करते हुए वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के जनसंपर्क अभियान की प्रशंसा की।

नंदनी का कमाल, योगासन में 14 गोल्ड मेडल किए अपने नाम

■ शासकीय स्कूल की छात्रा ने राष्ट्रीय मंचों पर दिखाई प्रतिभा, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने का लक्ष्य

रायपुर। रायपुर की बेटी कु. नंदनी निर्मलकर ने यह साबित कर दिया है कि सपनों को उड़ान देने के लिए बड़े संसाधनों नहीं, बल्कि बड़े हौसलों की जरूरत होती है। 12वीं कक्षा में अध्ययनरत नंदनी ने योगासन प्रतियोगिताओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 14 स्वर्ण पदक अर्जित किए हैं और आज वे जिले की युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं।

नंदनी का सफर एक साधारण छात्रा से राष्ट्रीय स्तर की योग खिलाड़ी बनने तक का है। शासकीय जे आर दानी विद्यालय, रायपुर में पढ़ाई करते हुए उन्होंने योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और कठिन अभ्यास, अनुशासन तथा समर्पण के बल पर एक के बाद एक सफलताएं हासिल कीं। वर्ष 2021 से लेकर 2025-26 तक उन्होंने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर स्वर्णिम उपलब्धियां अपने नाम कीं।

खेलो इंडिया, योगासन भारत, एसजीएफआई, योगा ओलंपियाड और वेस्ट ज़ोन नेशनल योगासन प्रतियोगिता जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर उनका प्रदर्शन लगातार उत्कृष्ट रहा है।

नंदनी अपनी सफलता का श्रेय जिला प्रशासन, अपने योग गुरु डॉ. छगनलाल सोनवानी, योग प्रशिक्षक सूर्य कुमार तथा प्राचार्य डॉ. हितेष दिवान को देती हैं। उनका मानना है कि सही दिशा और निरंतर अभ्यास से कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नंदनी का संदेश भी उतना ही प्रेरणादायक है। वे कहती हैं कि योग केवल प्रतियोगिता जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि स्वस्थ, सकारात्मक और अनुशासित जीवन जीने का आधार है।

महाराजबंद तालाब एसटीपी का कार्य पूर्ण नहीं करने पर रुकेगा भुगतान

रायपुर। निर्धारित तिथि तक यदि महाराजबंद तालाब एसटीपी का कार्य पूरा नहीं किये जाने पर महापौर मीनल चौबे ने निर्माणाधीन कंपनी का भुगतान रोके जाने की चेतावनी दी है। महापौर शहर के निगम के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास व सफाई व्यवस्था का जायजा ले रही थी।इसी अभियान के तहत महापौर मीनल महाराजबंद तालाब एसटीपी का अवलोकन करने पहुंची थी। यह एससटीपी 10 जुलाई तक शुरू होने का है।

महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से महाराजबंध तालाब में निर्माणाधीन 3 एमएलडी क्षमता के एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कार्य की प्रगति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। महापौर ने कार्य की कछुआ छाप गति देखकर इसे लेकर अनुबंधित ठेकेदार मेसर्स समृद्धि वाटर वर्कस प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि को कड़ी फटकार लगायी और तत्काल अतिरिक्त श्रमिक लगाकर शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस पर महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कार्य उक्त निर्धारित समयावधि 10 जुलाई तक पूर्ण नहीं होने पर सम्बंधित अनुबंधित ठेकेदार मेसर्स समृद्धि वाटर वर्कस लिमिटेड के भुगतान पर रोक लगाने की कड़ी कार्यवाही किये जाने की बात कही।

महापौर ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कार्य नियत समय तक पूर्ण नहीं होने पर करने के कड़े निर्देश रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सम्बंधित अभियंताओं को दिए हैं। इस दौरान नगर निगम जोन 5 जोन अध्यक्ष अम्बर अग्रवाल, जोन कमिश्नर श्री खीरसागर नायक, स्मार्ट सिटी उप अभियंता श्री योगेन्द्र साहू, श्री शुभम तिवारी, जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री संदीप वर्मा की उपस्थिति थे।

बिरगांव ननि में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में भाजपा का घेराव

बिरगांव, रायपुर। बिरगांव नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, लूट-खसोट एवं जनसुविधाओं की बदहाल स्थिति के विरोध में भारतीय जनता पार्टी बिरगांव एवं माँ बंजारी मण्डल के तत्वावधान में मंगलवार, 23 जून 2026 को प्रात: 11ः00 बजे बुधवारी बाजार, बिरगांव में नगर निगम का घेराव एवं विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं, विकास कार्यों में अनियमितताओं तथा प्रशासनिक उदासीनता को लेकर आम जनता में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे गंभीर प्रश्नों के बीच भाजपा द्वारा जनता की आवाज बुलंद करने के उद्देश्य से यह आंदोलन आयोजित किया जा रहा है।

इस अवसर पर नगर निगम में हुए कथित भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर महापौर के इस्तीफे की मांग प्रमुख रूप से उठाई जाएगी।

भारतीय जनता पार्टी बिरगांव एवं माँ बंजारी मण्डल ने क्षेत्र के नागरिकों, प्रबुद्धजनों, सामाजिक संगठनों एवं कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस जनहितकारी आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पावर कंपनी में हुआ योगाभ्यास

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य श्री विवेक गनोदवाले तथा प्रबंध निदेशकगण श्री एस.के. कटियार एवं श्री राजेश कुमार शुक्ला ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन और संतुलित दिनचर्या का संदेश दिया। कार्यक्रम में विभिन्न योगासनों एवं प्राणायाम का अभ्यास किया गया तथा नियमित योग को जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया गया।

पावर कंपनी मुख्यालय स्थित लोड डिस्पेच सेंटर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रशिक्षक डॉ. आनंद भारतीय ने योग प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास करवाया। इसके पश्चात कार्यपालक निदेशक श्री संजय पटेल ने शीर्षासन एवं मयूरासन प्रस्तुत किया, वहीं नन्हीं बच्ची विराध्या वर्मा ने सेतुबंधासन का प्रदर्शन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। गुढ़ियारी के खेलन यादव ने बकासन तथा सेवानिवृत्त कर्मी श्री मूल सजीवन शर्मा ने भी शीर्षासन प्रस्तुत किया।अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डायटिशियन सुश्री शिल्पी गोयल ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त धूप, स्वच्छ हवा एवं शुद्ध जल के महत्व पर प्रकाश डाला। योगाभ्यास के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की कार्यालय सहायक सुश्री अनिता गेडाम तथा जनरेशन कंपनी के अधीक्षण अभियंता एम.पी. नायक को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक के.एस. मनोठिया, मुख्य अभियंता रश्मि वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एच.एल. पंचारी, डीजीएम पंकज सिंह, एसई पंकज चौधरी तथा एई रजनीश चौबे उपस्थित थे। मंच संचालन डीजीएम (जनसंपर्क) श्री गोविन्द पटेल ने किया।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

प्रशासन की तत्परता से सुरक्षित हुआ नाबालिग का भविष्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा के उन्मूलन के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग तथा चाइल्ड हेल्पलाइन के समन्वित प्रयासों से राज्यभर में बाल विवाह रोकथाम की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बलरामपुर जिले के विकासखंड कुसमी अंतर्गत ग्राम पंचायत कोरंधा में एक नाबालिग बालिका का बाल विवाह समय रहते रुकवाकर उसके सुरक्षित एवं उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित क्षेत्र में नाबालिग बालिका का विवाह तय किए जाने की सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन तथा पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान बालक एवं बालिका दोनों की आयु विवाह के लिए निर्धारित वैधानिक आयु से कम पाई गई।

बीरगांव नगर निगम में योग शिविर का आयोजन

रायपुर। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर पालिक निगम बीरगांव द्वारा भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महापौर श्री नंदलाल देवांगन, आयुक्त श्री युगल किशोर उर्वशा, कार्यपालन अभियंता श्री बी.एल. देवांगन, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर योगाभ्यास किया। कार्यक्रम के दौरान योग प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न योगासनों एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया गया तथा योग के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभों की विस्तृत जानकारी दी गई। उपस्थित प्रतिभागियों को बताया गया कि योग स्वस्थ जीवन, मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच का आधार है तथा इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना समय की आवश्यकता है। योग शिविर के उपरांत सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों द्वारा पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया गया। इस अवसर पर हरित एवं स्वच्छ वातावरण के निर्माण हेतु अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प भी लिया गया।महापौर श्री नंदलाल देवांगन ने अपने संबोधन में कहा कि, योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति स्वस्थ एवं निरोग रहता है तथा समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।आयुक्त श्री युगल किशोर उर्वशा ने कहा कि योग एवं पर्यावरण संरक्षण दोनों ही स्वस्थ और समृद्ध जीवन के आधार हैं।

महिला आयोग की सुनवाई में कई मामलों का हुआ निराकरण

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य श्रीमती प्रियम्वदा सिंह जूदेव ने आज जशपुर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महिला उत्पीड़न एवं अन्य प्रकरणों की सुनवाई की। प्रदेशभर में आयोजित सुनवाई में 401 मामलों पर विचार किया गया, जिनमें जशपुर जिले के 10 प्रकरण शामिल रहे। सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण मामले में आयोग ने छह वर्षों से साथ रह रहे एक युगल के विवाह की प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए। मामले में अनावेदक, जो वर्तमान में सेना में कार्यरत है, ने आवेदिका के साथ लंबे समय से सहजीवन में रहने और उनसे एक पुत्री होने की बात स्वीकार की। आयोग के समक्ष आवेदिका ने एफआईआर दर्ज कराने के बजाय विधिवत विवाह कराने की इच्छा जताई, जिस पर अनावेदक ने सहमति दी। आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को दोनों पक्षों के विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ कर दो माह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही अनावेदक को प्रत्येक माह 10 हजार रुपए भरण-पोषण राशि जमा कराने का आदेश दिया गया।

उद्योग मंत्री ने सड़क डामरीकरण का कार्य प्रारंभ कराया

रायपुर। प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज नगर निगम कोरबा के वार्ड क्र. 40 पाड़ीमार वार्ड में सड़क डामरीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर महापौर संजूदेवी राजपूत उपस्थित थी। उन्होंने डामरीकरण कार्य के दौरान गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने एवं शीघ्र कार्य को पूर्ण किये जाने के निर्देश मौके पर अधिकारियों को दिये। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अनवरत रूप से किये जा रहे विकास कार्यों की कड़ी में निगम के बालको जोन अंतर्गत वार्ड क्र. 40 पाड़ीमार क्रमांक 01 में 25 लाख रूपए की लागत से राजेश ठाकुर के घर से बरगद चौक होते हुये इंदिरा मार्केट मुख्य मार्ग तक सड़क डामरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने इस मौके पर अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री रेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के आशीर्वाद से विगत ढाई वर्ष के दौरान नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न मदों के अंतर्गत लगभग 1000 करोड़ रूपये के विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें अनेक कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, अनेक प्रगति पर हैं तथा शेष कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहे हैं। उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने अपने उद्बोधन में कहा कि निगम क्षेत्र में 15 करोड़ रूपये के सड़क डामरीकरण कार्य कराये जाने हैं,।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर छत्तीसगढ़ से गूंजेगा हरित भारत का संदेश

रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर 23 जून को छत्तीसगढ़ में खेल और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बीएसएफ कैंप, नया रायपुर स्थित ग्राम पलौद में विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे होगा। मुख्यमंत्री श्री साय की उपस्थिति से खिलाड़ियों, खेल संगठनों तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों का उत्साह बढ़ेगा। भारतीय ओलंपिक संघ के आह्वान पर इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 2036 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस आयोजन के माध्यम से खिलाड़ियों और युवाओं को खेलों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। वृक्षारोपण अभियान प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने, जैव विविधता संरक्षण तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का मानना है कि मुख्यमंत्री की सहभागिता से प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को नई प्रेरणा मिलेगी।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना

आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए सराहनीय पहल

एल.डी.मानिकपुरी, डॉ. ओम प्रकाश डहरिया

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना प्रदेश के लाखों भूमिहीन परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। यह योजना न केवल जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि उनके जीवन में आत्मविश्वास, स्थिरता और बेहतर भविष्य की नई उम्मीद भी जगा रही है।

प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित की जाती है। यह राशि ऐसे परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बन रही है, जो सीमित आय और अस्थायी रोजगार के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। दैनिक जरूरतों की पूर्ति से लेकर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं घरेलू खर्चों तक, यह सहायता राशि परिवारों को राहत प्रदान कर रही है।

आर्थिक तंगी के कारण जिन परिवारों के लिए भविष्य की योजनाएं बनाना कठिन था, उनके लिए यह योजना नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। कई हितग्राही इस राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और घरेलू आवश्यकताओं पर कर रहे हैं, वहीं कुछ परिवार राशि का एक हिस्सा बचाकर स्वरोजगार या छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने की योजना भी बना रहे हैं। इससे आत्मनिर्भरता की दिशा में उनके कदम मजबूत हो रहे हैं।

योजना से लाभान्वित हितग्राहियों का कहना है कि उन्हें पहले इस तरह की सहायता की उम्मीद नहीं थी, लेकिन राज्य सरकार की जनकल्याणकारी पहल ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। उन्हें आर्थिक संबल मिला है, बच्चों के भविष्य के प्रति भरोसा बढ़ा है और परिवार को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना के अंतर्गत करीब 6 लाख हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें बैगा-गुनिया समुदाय के हितग्राही भी शामिल हैं। योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्रों में निवास करने वाले पात्र परिवारों को भी मिल रहा है।

योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूर, चरवाहा, नाई, धोबी, मोची तथा वनोपज संग्राहक आदि पात्र माने गए हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए।

हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना उनके जैसे भूमिहीन मजदूर परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

छात्रवृत्ति परीक्षा में 177 बच्चों का चयन, राज्य में तीसरा स्थान

रायपुर,। बस्तर जिले ने राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26 में ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। कलेक्टर श्री आकाश छिकारा और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रतीक जैन के मार्गदर्शन में तैयार की गई सुनियोजित रणनीति और शिक्षकों की सतत मेहनत के परिणामस्वरूप जिले के 177 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इस उपलब्धि के साथ बस्तर ने पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है।

यह सफलता इसलिए भी विशेष है क्योंकि पिछले वर्ष जिले से केवल दो विद्यार्थियों का चयन हुआ था, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 177 तक पहुंच गई है। एक वर्ष में लगभग 90 गुना वृद्धि ने बस्तर के शिक्षा मॉडल को प्रदेशभर में चर्चा का विषय बना दिया है। परीक्षा में चयनित सभी विद्यार्थियों को अब केंद्र सरकार की ओर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रतिमाह एक हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक छात्र को प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी आगे की शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी। ब्लॉक स्तर पर भी उल्लेखनीय प्रदर्शन देखने को मिला। बकावंड विकासखंड ने अकेले 130 विद्यार्थियों के चयन के साथ न केवल जिले में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.